कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

आवरण कथा

भारत बंद पूर्णतः सफल..... 6

श्रद्धांजलि

सुदर्शनजी नहीं रहे..... 14

राष्ट्रवाद के सुन्दर–दर्शन थे सुदर्शन
प्रभात झा..... 16

लेख

दो उपलब्धियां, एक अपेक्षा
लालकृष्ण आडवाणी..... 18

कांग्रेस की विदाई का वक्त
हृदयनारायण दीक्षित..... 20

राजनीति का खतरनाक रूप
ए. सूर्यप्रकाश..... 22

अन्य

भाजपा अनु. जाति मोर्चा सम्मेलन, दिल्ली..... 24

विवेकानंद युवा विकास यात्रा..... 25

भाजपा, मध्य प्रदेश कार्यसमिति बैठक (खंडवा)..... 29

ऐतिहासिक चित्र

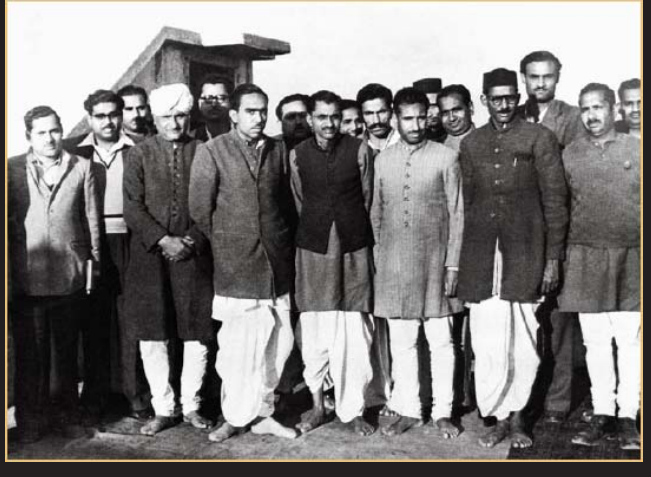

भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ नेताओं के साथ पं. दीनदयाल उपाध्याय

शिक्षित कौन ?

अनेक लोग स्वयं को शिक्षित और प्रगतिशील दिखाने के चक्कर में अपने हिन्दू प्रतीकों और नामों की उपेक्षा करते दिखते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी ने एक बार यह कथा सुनायी।

गाँव में रहने वाले एक निर्धन सज्जन ने अनेक कष्ट उठाकर भी अपने बच्चों को पढ़ाया। सौभाग्य से उनका एकमात्र पुत्र पढ़-लिखकर उच्च अधिकारी बन गया और एक बड़े शहर में उसकी नियुक्ति भी हो गयी। उचित समय पर उन्होंने पुत्र का विवाह किया। विवाह के बाद वह युवक पत्नी सहित शहर में ही रहने लगा।

दो साल इसी प्रकार बीत गये, एक दिन उन्हें समाचार मिला कि उनके बेटे के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। वे बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने पौत्र को देखने की इच्छा से शहर की ओर चल दिये।

जिस समय वे अपने बेटे की कोठी पर पहुँचे, वह अपने मित्रों के साथ बैठा चाय पी रहा था। जब उसने अपने पिता को आते हुए देखा, तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि मेरे ये मित्र क्या सोचेंगे कि ऐसा गँवार और निर्धन व्यक्ति उसका पिता है। उसने एक नौकर को भेजा, जिससे वह पिताजी को पिछले दरवाजे से अंदर ले आये।

जब एक मित्र ने आंगतुक के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि ये हमारा पुराना घरेलू नौकर है और गाँव से आ रहा है। उसके पिता ने यह सुन लिया। वे सबके सामने गुस्से में बोले : मैं कौन हूँ, यह इसकी माँ से पूछ लो। इतना कहकर वे अपना सामान उठाकर बिना पौत्र को देखे वापस चले गये।

इस घटना का संदेश है कि अच्छी शिक्षा वही है, जो संस्कारों को जीवित और जाग्रत रखे। ऐसी उच्च शिक्षा का क्या लाभ, जिससे व्यक्ति अपने धर्म, संस्कृति और परिवार से ही कट जाये।

-'श्री गुरुजी बोधकथा' से साभार

व्यंग्य चित्र

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

इनका कहना है...

''हम यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग करते हैं कि एफडीआई, डीजल और एलपीजी को लेकर गिए गए फैसलों को वापस ले तथा भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर सरकार फैसले वापस नहीं लेती तो हम अपने संघर्ष को और तेज करेंगे।'

-नितिन गडकरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

''जब भी कोई मुझसे पूछता है: राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के मुख्य योगदान को आप कैसे निरुपित करेंगे तो सदैव मेरा उत्तर रहता है: भारत की एकदलीय प्रभुत्व वाली राजनीति को द्विध्रुवीय राजनीति में परिवर्तित करना।'

-लालकृष्ण आडवाणी, अध्यक्ष, भाजपा संसदीय दल

''एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार-मुक्त थी, लोगों के प्रति जवाबदेह के साथ-साथ पारदर्शी थी परन्तु यूपीए सरकार ने सारी सीमाएं लांघ ली है जिससे अब इस सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक हो गया है।''

-राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

सम्पादकीय

जनता विकल्प खोज रही है

मुलायम सिंह और मायावती के हाथ में है यूपीए सरकार और मध्यावधि चुनाव। स्थिति यह है कि ममताजी ने समर्थन वापिस लिया तो उसके बाद मुलायम सिंह और मायावती उतनी ही जोर से बोलने लगे कि यूपीए को अभी हमारा समर्थन है। यहां एक बात तो स्पष्ट है कि अब कांग्रेस के साथ जो भी समर्थन में खड़ा होगा वह कम से कम जनता का समर्थन नहीं ले पायेगा। जनता कांग्रेस से पिंड छुड़ाना चाहती है, पर स्थिति यह है कि जनता की भावनाओं के साथ सपा-बसपा सहित सभी यूपीए के घटक खिलवाड़ कर रहे हैं।

कांग्रेस चाह रही है कि कैसे भी सत्ता में बनी रहे। उसका कारण है कि सिर पर गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनाव हैं। इन चुनावों में कांग्रेस की हालत बहुत पतली रहेगी। यह भाजपा का नहीं, जनता का दावा है। कांग्रेस समझ रही है इसके बाद उनकी और उनके दल की हालत और भी खराब हो जाएगी। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उनके अनेक सांसद दबी जुबां से कहते हैं कि डॉ. मनमोहन सिंह तो गांधी जी के सपने को साकार करने में लगे हैं। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत का गांव महंगाई की मार से कराह रहा है। ग्रामीण जीवन के परिवेश का ध्यान कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार कतई नहीं रख रही। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों में घृणा का भाव सहज पैदा हो रहा है। कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद विघटित करने की गांधी जी की इच्छा डॉ. मनमोहन सिंह इस तरह से अवश्य पूरा कर देंगे।

शायद कांग्रेस इस सच्चाई को समझते हुए भी आखिर क्या कर सकती है? कांग्रेस असहाय है। श्रीमती सोनिया गांधी जहां शरीर से अस्वस्थ हैं, वहीं कांग्रेस के युवराज को देश अभी मानसिक रूप से परिपक्व मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस वैसे भी ''दो लोगों'' की पार्टी है। अगर थोड़ा हटकर सोचें तो क्या कांग्रेस मां-बेटे की पार्टी नहीं है? यह बात भी स्पष्ट हो गई बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव सहित दिल्ली निकाय चुनावों की अग्नि परीक्षा में सोनिया जी एवं राहुल जी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनावों में तो भाजपा जीत ही रही है, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? कांग्रेस देश के इस मर्म को समझे या नहीं समझे पर देश पूरी तरह समझ चुका है। आज देश विकल्प चाहता है, पर यूपीए इस संकल्प से पीछे है। कांगेस तो इसलिए सत्ता में बने रहना चाहती है कि, उन्हें ''मोटी रकम'' मिलती रहे। कांग्रेस को रकम चाहिए पर देश से उन्हें कोई मतलब नहीं।

आजकल जिस भाषा का प्रयोग डॉ. मनमोहन सिंह, स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी के साथ-साथ चिदम्बरम कर रहे हैं उससे यह बात तो स्पष्ट हो रही है कि 'कांग्रेस' लकवाग्रस्त हो चुकी है। वह आज तो उठने की स्थिति में नहीं है, पर जिनकी सत्ता में आने की संभावना है, उन्हें अवश्य सम्भालना चाहिए। भारत के आम नागरिकों का एक ही स्वर है कि उन्होंने पूर्व में कभी केन्द्र में ऐसी सरकार नहीं देखी। स्थिति की भयावहता इस कदर है कि भीड़ भरे सेमिनार में देश के प्रधानमंत्री के सामने महंगाई से त्रस्त जनता की भावना के रूप में एक युवक ने सरेआम कपड़े उतार दिए। इसके बाद भी डॉ. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी न समझें तो न समझें, पर जनता की समझ इतनी बढ़ गई है कि वह सरेआम कुछ भी कर सकती है। देश कांग्रेस से दुखी है और चाहता है कि देश से कांग्रेस मुक्त हो। अब ऐसा समय आ ही गया है। हम सभी को हर दृष्टि से तैयार रहना होगा और रहेंगे भी। ■

भारत बंद पूर्णतः सफल

यूपीए की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध समूचा विपक्ष एकजुट

-संवाददाता द्वारा

20 सितम्बर 2012 को 'भारत बंद' कई मायनों में अभूतपूर्व व ऐतिहासिक रहा। डीजल की कीमतों में वृद्धि, सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सीमित किए जाने व बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के यूपीए सरकार के निर्णय के विरोध में आयोजित इस बंद का एक ओर जहां देश की जनता ने व्यापक समर्थन किया वहीं भाजपानीत राजग, यूपीए के सहयोगी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, समाजवादी पार्टी व वामपंथी दलों के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर वर्षों बाद विपक्षी एकजुटता का अद्भुत नजारा दिखा। मंच से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी, राजग संयोजक श्री शरद यादव, भाकपा नेता श्री एबी बर्धन, माकपा नेता श्री सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं ने सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किए। बंद से पूरे देश की रफ्तार थम गई। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। यातायात सेवाएं ठप्प रहीं। बंद को सफल बनाने के लिए समर्थकों ने कई अनोखे तरीके अपनाकर विरोध दर्ज किया। बेगूसराय में एक विधायक ने करीब एक किलोमीटर तक लोगों को बैठाकर खुद रिक्शा चलाया तो पटना में भाजपा के समर्थकों ने बैलगाड़ी की सवारी की। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद साइकिल की सवारी कर भाजपा कार्यालय पहुंचे। भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं के पटना में बैलगाड़ी की सवारी कर अपना विरोध जताया। इस दौरान बैलगाड़ी पर विभिन्न प्रकार की सब्जी के साथ-साथ रसोई गैस के सिलेंडर भी रखे गए थे। मध्यप्रदेश के इंदौर में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर चूल्हे पर रोटियां सेंकी तथा सिगड़ी पर चाय बनाई। अमृतसर में भाजपा सांसद श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने गैस सिलेंडरों की अर्थी निकालकर यूपीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। हम यहां प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों में संपन्न हुए भारत-बंद से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कर रहे हैं :

हम अपने संघर्ष को और तेज करेंगे : नितिन गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में 20 सितम्बर को विभिन्न दलों के बंद को अभूतपूर्व सफल बताते हुए कहा कि आपातकाल के बाद पहली बार अलग-अलग विचारों वाले दल एक साथ आए हैं और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

श्री गडकरी ने कहा कि कैग की रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रमंडल खेल, कोयला ब्लॉक आवंटन और टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला से देश को 4 लाख 38 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जिसके कारण यूपीए सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अब जोड़-तोड़ कर अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। कोयला मामले में कैग की रिपोर्ट को लेकर मचे बवाल से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने विदेशी किराना स्टोरों को आमंत्रित करने का 'आत्मघाती' कदम उठाया है। भाजपा अध्यक्ष श्री गडकरी ने कहा, 'हम यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग करते हैं कि एफडीआई, डीजल और एलपीजी को लेकर गिए गए फैसलों को वापस ले तथा भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर सरकार फैसले वापस नहीं लेती तो हम अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। यह सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों को बर्बाद करना चाहती है।

दिल्ली

डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ाने, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दिए जाने व केन्द्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनैतिक दलों के आह्वान पर 20 सितम्बर को भारत बंद के दौरान दिल्ली में अभूतपूर्व बंद रहा। प्रदेश भाजपा के 50 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर जगह-जगह धरना-प्रदर्शन किए। सौ से ज्यादा स्थानों पर सरकार और महंगाई का पुतला जलाया गया।

प्रदेश भाजपा की ओर से चांदनी चौक के टाउन हॉल पर आयोजित धरना-प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में प्रधानमंत्री निवास की ओर कूच कर रहे हजारों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लाल किला चौक पर गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस अब ऑल इंडिया कोयला कांग्रेस बन चुकी है। इस सरकार का आम जनता से कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस का गरीब विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। सरकार लोकतंत्र का रास्ता भूल गई है और लूटतंत्र में जुट गई है। कांग्रेस के राज में पांच लाख करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने रिटेल में एफडीआई, रसोई गैस, डीजल, बिजली के दामों में बढ़ोतरी तुरंत वापस लेने की मांग की।

एनडीए के संयोजक श्री शरद यादव ने कहा कि यूपीए सरकार देश पर राज करने का अपना अधिकार खो चुकी है। इतनी भ्रष्ट और जनविरोधी सरकार उन्होंने अपने जीवन में नहीं

देखी। यह सरकार चोरी और सीनाजोरी के रास्ते पर चल रही है। इसका रास्ता तानाशाही की ओर जाता है। गिरफ्तारी देने वालों में दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, प्रदेश महामंत्री रमेश विधूड़ी व प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सहित अनेक नेतागण भी शामिल थे।

करोलबाग इलाके में जिला अध्यक्ष और पार्षद राजेश भाटिया, स्थायी समिति अध्यक्ष योगेंद्र चंदोलिया, निर्माण समिति अध्यक्ष रविन्द्र गुप्ता व विजय पंडित के नेतृत्व में जगह-जगह धरना-प्रदर्शन हुआ। बंद के दौरान जनकपुरी विधानसभा में निगम पार्षद एवं प्रदेश महामंत्री आशीष सूद के नेतृत्व में सभी बाजारों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाल कर भारत बंद को अभूतपूर्व सफल बनाया। कार्यकर्ता हाथों में प्लेकार्ड्स लिये थे और मनमोहन सिंह इस्तीफा दो, जनविरोधी कांग्रेस सरकार- नहीं चलेगी आदि के नारे लगा रहे थे। यहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतले फूंके गये। महावीर एंकलेव, सीतापुरी, इन्द्रा पार्क, चाणक्य प्लेस, विरेन्द्र नगर, शिव नगर, जनकपुरी सहित सभी बाजारों में पूर्ण बंद रहा। रोहिणी में भी बंद पूरी तरह से सफल रहा। यहां रिठाला के विधायक कुलवंत राणा और रोहिणी जोन चेयरमैन प्रवेश वाही के नेतृत्व में सुबह से ही सैंकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। रोहिणी सैक्टर-16 व 17 की मार्किट को शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व सोनिया गांधी के पुतले जलाए गए।

भारत बंद का असर कनॉट प्लेस, जनपथ समेत अन्य वीवीआईपी इलाकों में भी देखा गया। हमेशा से लोगों से खचाखच भरा रहने वाला कनॉट प्लेस सुनसान रहा। दुकानों के बाहर ताले जड़े थे। जनपथ मार्केट प्लेस सुनसान रहा। दुकारों के बाहर ताले जड़े थे। जनपथ मार्केट और खान मार्केट भी बंद रहे।

उत्तर प्रदेश

केन्द्र सरकार द्वारा डीजल के दामों में वृद्धि, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी और सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटाए जाने के विरोध में भाजपा का 20 सितम्बर को उत्तर प्रदेश में भी असर दिखाई दिया। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं की अगुआई कर पदयात्रा निकाला और एफडीआई का विरोध किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के सड़क पर आने के चलते बाजार पूरी तरह बंद रहे। रेल और सड़क यातायात अवरूद्ध रहे। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, समेत दूसरे शहरों में कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल किया। कार्यकर्ताओं के बड़ी संख्या में जमा होने के कारण आगरा-ग्वालियर राजमार्ग अवरूद्ध रहे। राजधानी सहित कई स्थानों पर बड़े बाजार बंद रहे। वाराणसी में भी कई जगहों पर दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। केन्द्र सरकार के लिए बुद्धि-शुद्धि यज्ञ भी हुआ। बड़े शहरों में ऑटो, टैक्सी चालकों ओर व्यापारी संगठनों के बंद में शामिल होने से बंद पूर्णत: सफल रहा।

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एफडीआई के मुद्दे पर जहां ममता बनर्जी बधाई की पात्र है, वहीं सोनिया गांधी की खामोशी दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया गांधी की रहस्यमयी खामोशी इस बात क संकेत है कि देश के करोड़ों दुकानदारों को सड़क पर ला देने वाले ये नीतिगत फैसले विदेशी दबाव में लिए जा रहे हैं। केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी तो विदेशी दबाव में किए गए सभी फैसलों की जांच करायी जाएगी।

कानपुर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के लिए 'ब्लैक फ्राइडे' बताते हुए कहा कि पिछले शुक्रवार को कांग्रेस ने विदेशी कंपनियों के दबाव में रीटेल में एफडीआई की घोषणा की थी तो वह उनके लिए गुड फ्राइडे था लेकिन अगले शुक्रवार को जब उनके सहयोगी दल वापस लेंगे तो यह शुक्रवार कांग्रेस के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित होगा।

मध्यप्रदेश

भाजपा द्वारा कांग्रेसनीत यूपीए सरकार की राष्ट्रविरोधी नीतियों, खुदरा क्षेत्र में विदेश निवेश, डीजल की मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, घोटालों के विरोध में भारत बंद के दौरान मध्यप्रदेश में बंद सफल और शांतिपूर्ण रहा। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रभात झा ने कहा कि आज भारत बंद के दौरान मध्यप्रदेश में किसी को सड़क पर नहीं निकलना पड़ा। जनता ने स्वयं

अपना कारोबार बंद कर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घोटाले एवं मंहगाई के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।

भोपाल संभाग को छोड़कर शेष प्रदेश में बंद के दौरान वाणिज्यिक, व्यावसायिक कारोबार बंद रहा। गतिविधियां स्वप्रेरित बंद रही। रीवा संभाग में सभी क्षेत्रों में बंद सफल रहा जिसके दौरान रैली निकालकर कर बंद का आह्वान किया गया। सतना में कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने नगर का भ्रमण कर व्यवसायियों से बंद में सहयोग की अपील की। सतना के सिमरिया चौराहे पर झुग्गी झोपड़ी एवं परिवहन प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेन्डर पर माला चढ़ाकर मूल्यवृद्धि का विरोध प्रदर्शन किया। नर्मदापुरम संभाग और होशंगाबाद में बंद शांतिपूर्ण रहा। उज्जैन संभाग में मण्डल स्तर पर बंद का आह्वान किया गया जिसका पूर्ण रूप से समर्थन किया गया। सुबह भ्रमण कर, रैली निकालकर एवं नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। शाजापुर में बंद के दौरान यूपीए सरकार की नीतियों का विरोध कर ट्रेन रोकी गई, एफडीआई की शवयात्रा निकाली गयी, नेशनल हाइवे पर चक्काजाम किया गया जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुये। इंदौर संभाग में शांतिपूर्वक बंद रहा एवं व्यापारियों ने बंद में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। जनता चौक राजबाड़ा पर जनता की भावनाओं के अनुरूप पार्टी के नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के प्रतीक कोयला घोटाला, रसोई गैस की राशनिंग के चलते कोयले व कण्डे के साथ भ्रष्टाचार के प्रतीक यूपीए सरकार के घोटाले व आम आदमी के घुटन के प्रतीक मंहगाई के पुतलों को लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर संभाग में मण्डल स्तर पर बंद पूरी तरह सफल रहा। सागर संभाग में बंद के दौर मोटर साइकिल रैली निकालकर बंद का आह्वान किया गया। यह रैली मोती नगर चौराहा से तीन बत्ती तक निकाली गई। जबलपुर संभाग में भारत बंद सफल रहा। मंडला में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने बंद का समर्थन करते हुए सुबह से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रख एफडीआई को विरोध दर्ज किया।

उत्तराखंड

भारतबंद का देहरादून सहित पूरे प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला। लगभग सभी दुकानें और निजी विद्यालय आदि में अभूतपूर्व बंद देखने को मिला। देहरादून के बाजारों में सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। घंटाघर पर सवेरे से ही केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी। बंद में भाजपा सहित सभी विपक्षी दल शामिल हुए। पूरे प्रदेश में बंद को जनता का पूरा समर्थन मिला। प्रदेश के सभी मैदानी व पर्वतीय नगरों, कस्बों में भी बंद का खासा असर देखने को मिला। रामनगर, हल्द्वानी, कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, विकासनगर, उत्तरकाशी, टिहरी आदि में भी बंद सफल रहा।

बिहार

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश और डीजल कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित भाजपानीत राजग के भारत बंद को व्यापक जनसमर्थन मिला। बिहार में बंद का प्रभावकारी असर दिखा। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रकट किया। पूरे प्रदेश में रेल यातायात बाधित रहे। बंद के दौरान भाजपा

के सैंकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में मिल गए। पटना, पूर्णिया, मुजफरपुर समेह प्रदेश के तमाम प्रमुख शहरों में ट्रेनों को रोका गया। दुकानें बंद रहीं। सरकारी दफ्तर वीरान रहे। सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। वाहन भी नहीं चले। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री रविशंकर प्रसाद ने पटना की सड़कों पर साइकिल चलाकर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया। भाजपा नेताओं ने अररिया में बैलगाड़ी की सवारी की और पूर्णिया में घुड़सवारी कर विरोध जताया। घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर गोबर के गोइठे पर लिट्टी सेंककर विरोध प्रकट किया।

राजधानी पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सी.पी.

ठाकुर, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती किरण घई, भाजपा सांसद श्री राधामोहन सिंह समेत बड़ी संख्या में राजग कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहे पर गिरफ्तारी दी।

ओडिशा

केन्द्र सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा की ओर से आहूत बंद कर ओडिशा पर व्यापक असर दिखा। राज्य के कई हिस्सों में यात्री और व्यावसायिक वाहन नहीं चले। रेल यातायात सेवा प्रभावित रही। राज्य के मुख्य व्यावसायिक केन्द्र कटक सहित कई स्थानों में दुकानें बंद रहीं। सरकारी और निजी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं भी बंद रहीं। प्रदर्शनकारीयों ने रैलियां और जुलूस निकाले और विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए। राजधानी भुवनेश्वर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में व्यापारिक समुदाय पर भाजपा आहूत भारत बंद का व्यापक असर दिखा। दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। केन्द्र सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री गोपीनाथ मुंडे के नेतृत्व में प्रदर्शन किए गए। विदर्भ में व्यापारियों व दुकानदारों ने बंद में बढ़चढ़कर भाग लिया।

राजस्थान

खुदरा व्यापार में एफडीआई और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा द्वारा आयोजित-भारतबंद का राजस्थान में व्यापक असर देखा गया। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के तमाम बड़े शहर-कस्बों में बंद को व्यापक समर्थन मिला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर भारत बंद में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जयपुर में रहे। बंद के दौरान राजधानी जयपुर में प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रामगंज बाजार में प्रवेश करने पर अवरोध उत्पन्न किया। कोटा में वॉलमार्ट स्टोर पर प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्च किया। वालमार्ट के स्टोर पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। यहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। अजमेर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

पंजाब और हरियाणा

संप्रग सरकार की ओर से डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि, रसोई गैस सब्सिडी में की गई कटौती व रिटेल सेक्टर में सीधे विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दिए जाने के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा किए भारत बंद के आह्वान का पंजाब में भी व्यापक प्रभाव देखने को मिला। वहीं हरियाणा में बंद का प्रदेश में असर रहा। दोपहर तक जगह-जगह केंद्र सरकार, महंगाई और एफडीआइ के पुतले फूंके गए। बंद के दौरान अमृतसर के हाल गेट में सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने गैस सिलेंडरों की अर्थी निकाल कर यूपीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उद्योग मंत्री अनिल जोशी ने भी सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। लुधियाना, बठिंडा, तपा व धूरी में बंद का प्रभाव दिखा। जालंधर में पूर्ण बंद रहा। शहीद भगत सिंह नगर जिले में भारत बंद का असर देखने को मिला। रूपनगर में तो कांग्रेस समर्थकों की दुकानें भी बंद देखी गई। पठानकोट व कपूरथला में पूर्ण बंद रहा।

बंद का लुधियाना, मुक्तसर, पटियाला, बठिंडा, फाजिल्का, अबोहर, मोगा, बरनाला, फरीदकोट, मानसा, संगरूर व बरनाला में खासा असर देखने को मिला। राजपुरा व गुरुहरसहाय में रेल यातायात बाधित रहा। अबोहर में सभी बाजार, कालेज, सरकारी व निजी स्कूल बंद रहे। कई स्कूलों में परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं। श्री मुक्तसर साहिब, मलोट व गिद्दड़बाहा में जहां शहर के अंदर के मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद रहे। निजी स्कूल बंद रहे। मोगा, बाघापुराना, निहाल सिंह वाला, धर्मकोट, बधनी कलां तथा कोट इसे खां में पूर्ण तौर पर बंद रहा। बसें बंद रही। संगरूर में बाजार बंद रहे।

मंडी गोबिंदगढ़ में पूर्ण बंद रहा। प्रदर्शनकारियों ने जीटी रोड पर चक्का-जाम किया। बरनाला व होशियारपुर जिले में बंद का व्यापक असर दिखा। उधर, हरियाणा में बंद का असर साफ दिखा। दोपहर तक जगह-जगह केंद्र सरकार, महंगाई और एफडीआइ के पुतले फूंके गए। सिरसा और सोनीपत में बंद का सबसे ज्यादा खासा असर देखने को मिला।

झारखंड

राष्ट्रव्यापी बंद का झारखंड में व्यापक असर रहा। बंद से पूरे प्रदेश की रफ्तार थम गई। पूरे प्रदेश में सैकड़ों बसें नहीं चलीं, 50 हजार ट्रकों का चक्का जाम रहा। टेम्पो और ऑटो के पहिये भी थमे रहे। राज्य की सड़कें वीरान रहीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा। कई जिलों में स्कूल से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक, बाजार व वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा। रेल सेवाएं भी बाधित रहीं। राज्य की लगभग चार लाख से अधिक थोक व खुदरा दुकानें बंद रहीं। सरकारी कार्यालयों में भी लोगों की उपस्थिति नगण्य दिखी। सचिवालय का भी यही हाल रहा। कई स्थानों पर बंद समर्थकों ने ट्रेनों को रोक विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी रांची स्वत:स्फूर्त बंद रही। राजधानी में 500 से अधिक कार्यकर्ता समेत पूरे प्रदेश में सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, उन्हें शाम में रिहा कर दिया गया। पश्चिम सिंहभूम में चाईबासा-रांची एनएच 75 पर वाहनों का परिचालन नहीं हुआ।

छत्तीसगढ़

भाजपा द्वारा 20 सितम्बर को आयोजित बंद छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण रहा। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और अंबिकापुर संभाग के शहरी क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। पॉवर हाउस और दुर्ग स्टेशन में रेल यातायात बाधित रहा। राजनांद गांव भी पूरी तरह बंद रहा। भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही बंद सफल कराने सड़कों पर निकल पड़े थ। बंद का समर्थन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स तथा कई व्यापारिक संगठनों ने किया था।

गुजरात

देशव्यापी बंद का असर गुजरात में भी साफ दिखाई दिया। भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही अलग-अलग स्थानों पर सड़कों पर उतरकर केन्द्र सरकार के इन फैसलों पर अपना विरोध दर्ज करते रहे। बड़ोदरा में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमन की अगुआई में एक रैली निकाली गई। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की सरकार ने जिस तरह भ्रष्टाचार किया है और महंगाई बढ़ाई है, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बंद के दौरान नवसारी संसदीय क्षेत्र के संसद सीआर पाटिल की अगुआई में भाजपा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सूरत से सटे उद्धना स्टेशन पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया जिससे रेल यातायात अवरूद्ध हुआ। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। बंद के समर्थन में सूरत के कपड़ा बाजार बंद रहे। साथ ही शहर के महीधर पूरा और मिनी बाजार जैसे प्रमुख बाजारों की दुकानें नहीं खुलीं।

कर्नाटक

भाजपा की ओर से डीजल के दाम में बढ़ोतरी, बहुब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति और सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या कम करने के विरोध में आयोजित भारत बंद के कारण कर्नाटक में बंद शांतिपूर्ण और सफल रहा। राजधानी बेंगलुरू में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी।

जम्मू-कश्मीर

भारत बंद के आह्वान का जम्मू में व्यापक असर देखने को मिला। जम्मू में अधिकतर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। यातायात सेवाएं ठप रही। बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। बंद के सभी मुद्दे आम आदमी से सीधे तौर पर जुड़े थे, लिहाजा शहर के अधिकतर क्षेत्रों में लोगों ने बिना किसी दबाव के अपनी दुकानें बंद रखीं। मिनी बस चालकों, थ्री व्हीलर व बस चालकों ने भी बंद पर अमल करते हुए वाहन सड़क पर नहीं उतारे। जम्मू के साथ लगते कस्बों में भी बंद रहा। विजयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूपीए विरोधी रैली निकाली। अखनूर में भी बंद का असर दिखा और कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। रामगढ़ में भी बंद का असर देखने को मिला। ■

भाजपा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

'कैग पर हमले रोकें'

भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 12 सितम्बर 2012 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी को ज्ञापन सौंप कर कोयला ब्लॉक आवंटन मुद्दे पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में- भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली एवं भाजपा सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी शामिल थे। हम इस ज्ञापन का पूरा पाठ यहां प्रकाशित कर रहे हैं :

श्री प्रणव मुखर्जी
महामहिम भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

बेहद दुख और चिन्ता व्यक्त करते हुए हम आपका ध्यान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विरूद्ध गत कुछ महीनों में और विशेषकर कोयला ब्लाकों के आबंटन तथा मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये कोयला उत्पादन बढ़ाने सम्बंधी कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद एक के बाद एक लगाये गये आरोपों की ओर आकर्षित कर रहे हैं।

संसद सदस्यों तथा कांग्रेस पार्टी के उच्च पदाधिकारियों और स्वयं प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कैग रिपोर्ट की आलोचना की है। कैग के बारे में खुले तौर पर राजनीतिक आकांक्षाएं रखने सहित अन्य बातें कही गई हैं। कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा करने कैग संस्थान के प्राधिकार को बार बार चुनौती दी गई है। प्रधानमंत्री द्वारा 27 अगस्त को संसद में और सार्वजनिक रूप से दिये गये वक्तव्य सर्वाधिक आघात पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने संसद मे कहा, ''कैग की टिप्पणियां स्पष्ट रूप से विवादास्पद'' हैं और ''कैग के निष्कर्षो में अनेक खामियां हैं।''

उसी दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया ''कैग की टिप्पणियां विवादस्पद हैं और लोकलेखा समिति में मामला आने पर उन्हें चुनौती दी जायेगी।''

प्रधानमंत्री, जो एक उच्च संवैधानिक पद धारण किये हुए हैं, इस प्रकार का वक्तव्य जारी करके वास्तव में लोकलेखा

समिति में द्विदलीय चर्चा को पूरी तरह से ध्रुवीकृत पार्टिसन चर्चा में बदल रहे है। इससे लोक लेखा समिति पूरी तरह से निष्क्रिय हो जायेगी। इसके परिणाम भारत के लोगों के प्रति इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार की सभी प्रकार की वित्तीय जवाबदेही के लिये बहुत ही अधिक खतरनाक होंगे। इससे कार्यरत लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली समाप्त हो जायेगी। एक उत्तरदायी विपक्षी पार्टी होने के नाते यह स्थिति हमें और भारत के नागरिकों को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।

राष्ट्रपति जी,

जुलाई, 1954 में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था, ''.....पहले से तयशुदा समय पर जब सरकार अनेक कल्याणकारी परियोजनाओं पर भारी धनराशि व्यय कर रही है.... यह अनिवार्य है कि हमारे द्वारा खर्च किये जाने वाले प्रत्येक रूपये का पूरा पूरा हिसाब रखा जाये। यह कहते हुए हमें संकोच हो रहा है कि यह महत्वपूर्ण कार्य, कोई भी कार्य सदैव मनपंसद नहीं होता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उनका कार्यालय करेगा। उसे प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उसे यह कार्य राष्ट्र के हितों में, बिना किसी भय या पक्षपात के, करना होगा।''

जून, 1954 में मद्रास में उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था : ''हमारा एक गरीब देश है, इसके संसाधन सीमित हैं और हम किसी प्रकार की फिजूलखर्ची करने लायक नहीं हैं और लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग को अपने कार्यों को जनता के लिये अधिकतम उपयोगिता के कार्यों के रूप में अंजाम देना होगा।'' उन्होंने आगे यह भी कहा, ''यदि मेरे पास लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों को देने के लिये कोई परामर्श है और वह परामर्श मैं उन्हें देने की धृष्टता करता हूं तो वह है: ' उच्च पदों पर आसीन लोगों को नाराज करने के डर से सच्चाई से पीछे मत हटो।'' वर्ष 1952 में जब कैग की किसी रिपोर्ट की संसद में एक सदस्य द्वारा आलोचना की गई थी, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने यह टिप्पणी की थी, ''वह (कैग) सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है और वह रिपोर्टों में सरकार की आलोचना कर सकता है। संसद में उसकी आलोचना करने से उसे ऐसा लगेगा कि उस विशेष पद को कमतर आंका गया है जो बिना भय या पक्षपात के अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिये उसे दिया गया है।''

यहां पर एक ऐसी घटना का स्मरण करना फायदेमंद सिद्ध होगा जब अध्यक्ष ने नियत्रंक और महालेखापरीक्षक के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणी को वापस लेने के लिये एक मंत्री को कहा था। 10 मार्च 1960 को जब रक्षा मंत्री नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट को ''द्वेषपूर्ण अत्युक्तिपूर्ण वक्तव्य' बताया था, तब विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं प्राप्त हुई थी जिनपर अध्यक्ष ने 14 मार्च, 1960 को निम्न विनिर्णय दिया था-

''संविधान के अधीन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को बिना भय या पक्षपात के इस सदन को रिपोर्ट देनी होती है और विभिन्न मामलों की जांच करनी होती है। व्यावहारिक तौर वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें वित्तीय पहलुओं पर सलाह मशविरा देता है, वह एक स्वतंत्र प्राधिकारी है जिसके आचरण की इस तरीके से निन्दा नहीं की जा सकती। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसे हटाये जाने, आदि के लिये विशेष उपबंध हैं, परन्तु अन्यथा उसकी टिप्पणियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जायेगा, चाहे जो कुछ भी वह कहे और चाहे उसके द्वारा कितनी भी कड़ी भाषा का उपयोग क्यों न किया गया हो।''

उसके बाद रक्षा मंत्री ने बिना शर्त खेद व्यक्त किया और अपनी टिप्पणियों को वापस ले लिया। राष्ट्रपति जी, तत्कालीन वित्त मंत्री होते हुए आपने वर्ष 2011 में हनोई में, एशिया डेवलपमेंट बैंक की वार्षिक आम बैठक में कहा था, इसे (भष्ट्राचार) समाप्त किया जाना चाहिए ताकि प्रणाली में लोगों का विश्वास बना रहे और सरकारी कार्यकरण के अनेक पहलू जवाबदेह, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त होने चाहिए। आपने यह भी कहा था, '' भारतीय प्रशासन प्रणाली संसद की लोक लेखा समिति और सरकार के लेखापरीक्षक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) जैसी संस्थानों के माध्यम से कडे नियंत्रित व संतुलित है।

अत: हम संविधान के रक्षक के रूप में आपके द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का अनुरोध करते हैं और न केवल कैग पर अपितु जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा तैयार की गई समूची संवैधानिक मशीनरी पर इस प्रकार के खतरनाक हमले बन्द करवाने का भी अनुरोध करते हैं। हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। ■

नहीं रहे रा.स्व.संघ के पूर्व सरसंघचालक कुप्प्. सी. सुदर्शन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक श्री कुप्पहल्ली सीतारामय्या सुदर्शन ने गत 15 सितम्बर 2012 को रायपुर में सुबह 6.55 बजे अपनी अंतिम साँस लेकर इस जगत से विदाई ली। सुबह जब अपना नित्य का टहलने का क्रम पूरा कर के वापस लौटे तभी वह कुछ थकावट और बैचेनी महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कुपहल्ली सीतारामय्या सुदर्शन जी का जन्म 18 जून 1931 को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था। 1954 से वह प्रचारक के तौर पर कार्यरत थे। सुदर्शन जी 10 मार्च 2000 को संघ के सरसंघचालक बने। 2009 मार्च में उन्होंने गिरते हुए स्वास्थ्य और बढती हुई आयु के कारण इस दायित्व से मुक्त होकर श्री मोहन भागवत को सरसंघचालक का दायित्व सौंप दिया था।

नागुपर में 16 सितम्बर 2012 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भूतपूर्व सरसंघचालक सुदर्शन जी के पार्थिव शरीर का स्थानीय गंगाबाई श्मशानघाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके कनिष्ठ बंधु के. एस. रमेश जी ने मुखाग्नि दी। संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में करीब दस हजार से अधिक लोगों ने अत्यंत शोकाकुल मन:स्थिति में सुदर्शन जी को अंतिम बिदाई दी। भू-तल पर राष्ट्रकार्यार्थ प्रकट हुई तेजपुंज ज्योति अग्नि में समा गई।

सुदर्शन जी की इच्छानुसार रायपुर में माधव नेत्रपेढी को उनके नेत्र दान किए गए।

अंतिम यात्रा

सुदर्शन जी के अन्तिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रेशिमबाग स्थित महर्षि व्यास सभागृह में रखा गया था। अंतिम यात्रा आरंभ होने के पूर्व के धार्मिक विधि के लिए दो बजकर तीस मिनट पर, महर्षि व्यास सभागृह के द्वार बंद कर, कुछ समय के लिए अंतिम दर्शन रोक दिया गया। उसी समय हल्की बारिश शुरु हुई, फिर भी लोग बाहर भीगते हुए शांति से कतार में खड़े थे। धार्मिक विधि समाप्त होने के बाद फिर महर्षि व्यास सभागृह के द्वार खोल दिए गए और अंतिम दर्शन के लिए नागरिकों को सभागृह में प्रवेश दिया गया। पौने तीन बजे के करीब भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राज्ययसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह, लोकसभा में भाजपा के उपनेता श्री गोपीनाथ मुंडे, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंतकुमार ने सुदर्शन जी को श्रद्धांजलि अर्पण की।

ठीक तीन बजे फूलों से सजे और सुदर्शन जी का छायाचित्र लगाए खुले ट्रक पर उनका पार्थिव रखा गया और अंतिम यात्रा गंगाबाई श्मशानघाट को निकल पड़ी। ट्रक पर सुदर्शन जी के भाई के. एस. रमेश तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ संघ के चुने हुए स्वयंसेवक सवार थे। रेशिमबाग संघ कार्यालय से गंगाबाई घाट तक के मार्ग पर लोग सुदर्शन जी का अंतिम दर्शन लेने के लिए खड़े थे।

गंगाबाई श्मशानघाट एक अलौकिक व्यक्तित्त्व के अंतिम संस्कार के लिए सिद्ध हुआ था। सुदर्शन जी का पार्थिव रखा ट्रक रेशिमबाग से श्मशानघाट आते समय मार्ग में जगनाडे चौक में नागरिकों ने शवयात्रा पर पुष्पवृष्टि की। ट्रक के पीछे शोकाकुल जनप्रवाह चलते समय, मन में सुदर्शन जी के साथ बिताए क्षणों का, उनके मार्गदर्शन का स्मरण कर रहा था।

गंगाबाई घाट पर पहुँचते ही, दाह संस्कार पूर्व की विधि आरंभ हुई। मा. सुदर्शन जी के कनिष्ठ बंधु रमेश जी ने वह विधि पूर्ण की। श्री रमेश जी ने ही सुदर्शन जी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी और देखते ही देखते एक योगी का पार्थिव शरीर ज्वालाओं से घिर गया। जिस पंचतत्त्व से निर्माण हुआ था, फिर उसी में मिल गया। जैसे, सागर से उठी

लहर फिर सागर में ही विलीन हो गयी हो। परमात्मा का एक दिव्य अंश, विशिष्ट कार्यार्थ इस भू-तल पर देह धारण कर आया था। उसे एक नाम मिलाया, एक पहचान मिली और 81 वर्ष के काल में सौंपा गया कार्य यथाशक्ति पूर्ण करने के समाधान में वह दिव्य अंश फिर परमात्मा में समा गया। लेकिन, 81 वर्ष में यह काया, अनेकों को जीवनादर्श का स्मरण करा गई अंतर्मन में बसी देशभक्ति की चिंगारी को धधकता शोला बना गई।

15 सितम्बर की रात 7 बजे मा. सुदर्शन जी का पार्थिव शरीर रायपुर से विशेष विमान द्वारा नागपुर लाया गया। नागपुर के महानगर संघचालक डॉ. दिलीप गुप्ता ने पार्थिव शरीर रेशिमबाग लाया। हवाई अड्डे पर भी सैकड़ों लोग, स्वयंसेवक उपस्थित थे। रेशीमबाग में पार्थिव शरीर महर्षि सभागृह में जनदर्शनार्थ रखा गया।

रा. स्व. संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने सुदर्शन जी को पुष्पांजलि अर्पण की। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांताक्का जी, पूर्व प्रमुख संचालिका प्रमिलाताई मेढे ने भी बंधुवत् ज्येष्ठ मार्गदर्शक को श्रद्धांजलि अर्पण की। रात करीब ९ बजे सरसंघचालक मोहन भागवत जी नागपुर पहुँचे। उन्होंने भी सुदर्शन जी को श्रद्धांजलि अर्पण की।

16 सितम्बर की सुबह से ही स्वयंसेवक और अन्य रेशिमबाग आने लगे। गंभीर मन:स्थिति में, मा. सुदर्शन जी की यादों का स्मरण करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने लगे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक जी सिंघल, महाराष्ट्र की विधानसभा के विपक्ष के नेता एकनाथ खडसे, भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अण्णासाहब मुरकुटे तथा अन्य लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पण की। आने वाले मान्यवर मोहन जी और भैयाजी को सांत्वना-भेंट देकर जाते थे। सह सरकार्यवाह श्री सुरेश सोनी और श्री दत्तात्रेय होसबोले, इंद्रेश जी, मधुभाई कुलकर्णी, राममाधव जी, मनमोहन जी, मदनदास जी आदि संघ के अधिकारी सभागृह में उपस्थित थे। देशभर से विविध क्षेत्रों के कार्यकर्ता, अधिकारी तथा संघ के अधिकारी सुदर्शन जी के अंतिम दर्शन के लिये आये थे।

सुदर्शन जी ने भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रभक्ति की ज्योत प्रज्जवलित करने के लिए अथक परिश्रम किए। उनके निधन से राष्ट्रवादी मुस्लिमों को अपना समर्थक खोने का दु:ख हुआ है। देश भर के विविध मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि श्रद्धांजलि अर्पण करने आए थे।

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, नागपुर के महापौर अनिल सोले, सांसद बलबीर पुंज, स्मृति इराणी, मौलाना बशिरुद्दीन, मौलाना शोएब कासमी, ज्येष्ठ संघ चिंतक मा. गो. वैद्य, ग्राहक पंचायत के अखिल भारतीय अध्यक्ष अरुण देशपांडे, महामंत्री सोमनाथ खेडकर, मार्गदर्शक राजाभाऊ, तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश भाजपा के ज्येष्ठ नेता कैलाश जोशी, बाबूलाल गौर, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, भारतीय मजदूर संघ के ज्येष्ठ नेता उदय पटवर्धन, महामंडलेश्वर निखिलेश्वरानंद, गुजरात प्रान्त संघचालक जयंतीभाई भडेसिया ने भी अंतिम दर्शन लिए। ■

भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का शोक-संदेश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक श्री कुप्प्. सी. सुदर्शन के निधन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक-संदेश में श्री गडकरी ने श्री सुदर्शन को एक महान विचारक एवं देशभक्त बताया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में संघ प्रचारकों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपकर राष्ट्रीय उत्थान के लिए संघ का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि श्री सुदर्शन स्वदेशी, बायो-फ्यूल और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के प्रबल समर्थक थे तथा देश के निचले पायदान के लोगों का विकास पाश्चात्य आर्थिक मॉडल की नकल किए बिना करना चाहते थे। श्री सुदर्शन के निधन से संघ में एक ऐसा शून्य उत्पन्न हुआ है जिसकी भरपाई अत्यंत कठिन है। उनका प्रयाण संघ में एक युग के अंत का द्योतक है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी का शोक संदेश

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि श्री सुदर्शन सही मायने में संत थे। उनके रूप में 21वीं सदी में महान शख्सियत ने अवतरण लिया। संघ व्यक्तित्व व राष्ट्रनिर्माण की प्रेरणा देता है। श्री सुदर्शन ने राष्ट्रनिर्माण में बड़ी भूमिका निभाई।

राष्ट्रवाद के सुन्दर-दर्शन थे सुदर्शन

प्रभात झा

O मलयाली थे। वे तेलगु, तमिल, कन्नड़ थे या असमिया थे, बंगाली थे या पंजाबी थे या फिर मराठी थे, या हिंदी बोली जाने वाली प्रांत के थे या अंग्रेजी-संस्कृत के साथ-साथ वे छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश के थे, इसका पता कोई लगा नहीं सकता क्योंकि इन सभी भाषाओं पर उनका नियंत्रण था। उन्होंने भारत की आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ लिया था। भारत माता उनके रोम-रोम में थी। सुदर्शन जी को भी भारत माता ने अपनी गोद में पालपोसकर हर अंचल की आंचल का अमृत पिलाया। उनका 'कुल' मातृभूमि की माटी थी। उन्होंने भारत को स्वयं अपने नेत्रों से एक नहीं अनेक बार देखने का अनथक प्रयास किया। 62 वर्ष तक अनवरत् संन्यासी भाव से देह को देश के लिए अर्पित कर उसकी रखवाली की भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व का नाम सुदर्शन जी है।

देश उनकी देह में धारण करता था, जिनके देह में राष्ट्रवाद की अखंड ज्योति सदैव जलती रहती थी और वह ''तमसो मां ज्योतिर्गमय'' की भाव से यायावर की तरह मां भारती की माटी को अपने माथे पर लगाकर प्रकृति की अर्पण में रात-दिन लगे रहते थी। सुदर्शन जी के देह में मां का वात्सल्य था, पिता की सुरक्षा थी, गंगाजल की पवित्रता थी, हिमालयीन भाव सी ऊंचाईयां थी, वे कर्ण की तरह दानी थे, दधीचि की तरह उन्हें देह दान करने का असीम सामर्थ्य था। वे जमीनी थे। वे यथार्थ थे। वे सच थे। वे तप थे। वे यज्ञ थे। वे समिधा थे। वे अर्चना, आराधना, राष्ट्रोत्थान के संग-संग 'माधव' की संतान थे। उनमें गोवर्धन पहाड़ उठाने की क्षमता थी, वहीं वे संधान के प्रति सदैव जागरूक रहते थे।

सुदर्शन जी, 'स्वदेश' थे। सुदर्शन जी 'सिख संगत' थे। सुदर्शन जी 'राष्ट्रीय मुस्लिम मंच' थे। सुदर्शन जी आरोग्य

और खेल के भी प्रतीक थे। वे शारीरिक थे। वे बौद्धिक थे। वे स्वदेशी थे। वे योगी थे। वे प्रयोगधर्मी थे। प्रयोग का प्रयास उनका मूल स्वभाव था। मूल में वे इंजीनियर होने के नाते रचनाधर्मी थे। वे नूतन के हामी थे पर पुरातन के संरक्षक भी थे। वे कावेरी, ताप्ती, नर्मदा सहित चंबल शिप्रा के साथ-साथ सभी नदियों के पुजारी थे। वैसे तो वे प्रकृति के पुजारी थे। सामान्य नहीं होता है स्वयं के प्रति वज्र होना। उनमें हनुमान सा साहस था तो वहीं भगवान श्रीराम की मर्यादा भी उनमें देखी जा सकती थी। वे मानवता के पुजारी थे। उनमें मानवों की पीड़ा पीने का अदम्य साहस था। वे समाज को अमृत व स्वयं के लिए जहर की अपेक्षा रखते थे।

आज इस भौतिकवादी युग में जब सत्ता और अधिकार के लिए मानवसंहार तक लोग करने में पीछे नहीं हटते, ऐसे दौर में भारत की धरा पर एक मानुष ऐसा भी आया जिसने अमानुषता के घोरतम कालिमा में एक मानुषता की ज्योति जलाने का ऐतिहासिक फैसला किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ''सरसंघचालक'' थे। विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संगठन के मुखिया थे। विश्व में भी संघ की शाखाएं लगती हैं। वे ऐसे संगठन के प्रमुख थे, जिसे संगठन ने देश को हिन्दू होने का गौरव बताया। वे उस संगठन के प्रमुख थे जिसने भारत की सांस्कृतिक चेतनाओं को विश्व के पटल पर जाग्रत रखने का और विश्व को भारत का महत्व समझाने के प्रयास में रात-दिन लगे रहे हैं। वे लाखों स्वयंसेवकों के प्रमुख थे। 'वे' आदेश थे। वे प्रश्न नहीं उत्तर थे। वे समस्या नहीं समाधान थे। खासकर वे सरसंघचालक उस समय थे जब देश में प्रधानमंत्री सहित अनेक मंत्री उनकी विचारधारा के थे। उन्हें उस दौरान की सत्ता का ऋषि भी कहा जा सकता है, पर वे सत्ता के प्रभाव से सदैव मुक्त रहे। वे चाहते थे कि सत्ता किसी की हो लेकिन वह ''राष्ट्रधर्म'' पर चले। 'भारत' ओझल नहीं हो। सत्ता के केन्द्रबिन्दु में भारत रहता है तो भारतीय और भारतमाता पर कभी आंच नहीं आ सकती। वे कहते थे सत्ता यदि अनुकूलता वाली है तो राष्ट्रीय यज्ञ में यज्ञ करने में सुविधा हो जाती है, और प्रतिकूलता वाली होती है तो थोड़ी बहुत कठिनाई

होती है। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक 'राष्ट्रीय मार्ग' है, जिस पर आज नहीं तो कल सभी को चलना है, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, क्योंकि पूजा पद्धति अलग-अलग हो सकती है, पर ईश्वर तो एक है। वो कहते हैं कि हमें हमारा राष्ट्रीय, भारतीय, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मार्ग कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर मनुष्य है, या मनुष्यों का समाज है तो वह इन तत्वों के बिना नहीं रह सकता। अत: हमें हमारे मार्ग पर, जिसे हमने (विजयादशमी) सन् 1925 में अपनाया था, उसे किसी भी परिस्थितियों में नहीं छोड़ना है। अंतत: सभी को संघ के राष्ट्रीय मार्ग पर आना ही है।

सुदर्शन जी को भारत माता ने अपनी गोद में पालपोसकर हर अंचल की आंचल का अमृत पिलाया। उनका 'कुल' मातृभूमि की माटी थी। उन्होंने भारत को स्वयं अपने नेत्रों से एक नहीं अनेक बार देखने का अनथक प्रयास किया। 62 वर्ष तक अनवरत् संन्यासी भाव से देह को देश के लिए अर्पित कर उसकी रखवाली की भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व का नाम सुदर्शन जी है।

सुदर्शन जी 'स्पष्ट' थे। वे कर्म और विचार के समन्वयक थे। वे केवल विचार नहीं बल्कि 'विचार' के व्यावहारिक ज्ञाता भी थे। वे समय काल परिस्थितियों के 'जनक' थे। वे ज्योतिषी शास्त्र के जहां ज्ञाता थे, वहीं वे अपनी 'छठवीं ज्ञान' की परीक्षा भी ज्योतिषियों के माध्यम से करते रहते थे।

वे जिज्ञासु थे। वे उत्सुकता के प्रतीक थे। वे आशा थे। वे प्रायोजित जीवन के नहीं नियोजित जीवन के धनी थे। वे बालबोध थे। उनकी जीवन की रस्सी या डोर में गठानें नहीं आती थीं। वे खुले उदार चित्त के स्वयंसेवक थे।

यह आसान नहीं होता कि जो राजा की स्थिति में हो, और वह राजा रहते हुए प्रजा रूपी जीवन जीने का अचानक निर्णय ले ले। वे भारत के ऐसे सरसंघचालक हुए, जिन्होंने क्राउन (ताज) के लिए संगठन और राष्ट्र को दांव पर नहीं लगाया बल्कि उपयुक्त समय आने पर उसे सुयोग्य व्यक्तित्व को सौंप दिया। अत: जब उनके मन में यह बात आ गई कि 'ताज' उसके सिर पर, जो 'शत-प्रतिशत' कार्य कर सके, तो उसे तत्काल सौंप दिया। आज राष्ट्रहित में यह है कि 'ताज' छोड़ दो, राजा का पद छोड़ दो और प्रजा बनकर जियो। यह अतुलनीय निर्णय वही कर सकता है जिस आत्मा में परमात्मा का भाव हो और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने की जिजीविषा हो। इस युग में यह कैसे संभव हुआ।

वे 'राजा' थे, पर उन्होंने ''धर दीन्ही चदरिया'' के भाव को जीवित रहते हुए सार्थक किया। हर गुरु सुयोग्य नेतृत्व को तराशता है। चाहे वह रामकृष्ण परमहंस हो, जब उन्हें युवा नरेन्द्र मिला तो उन्होंने उसे तराशा और स्वामी विवेकानंद बना दिया। वहीं समर्थ रामदास को एक सच्चे राष्ट्रभक्त की तलाश थी, जब उन्हें जीजाबाई का बेटा मिला तो उन्होंने उसे छत्रपति शिवाजी बनाने में देर नहीं की। उसी तरह राष्ट्रवाद के सुन्दर दर्शन को जब 'मोहन' रुपी स्वयंसेवक मिले तो उन्होंने उन्हें छत्रपति शिवाजी और स्वामी विवेकानंद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

ईश्वर ने उन्हें परमपूज्य बनने का अवसर दिया और जब उन्हें लगा कि अब नया परम पूज्य मिल गया तो उन्होंने अपने को भूतपूर्व बनाने में एक क्षण नहीं लगाया।

वे प्रजा के रूप में भी बैठे नहीं रहे। उन्होंने संघ कार्य को जारी रखा। प्रवास चलता रहा। सामान्य व्यक्ति की तरह वे सभी से चर्चा करने लगे। यह विलक्षण गुण उन्हें ईश्वर ने प्रसाद के रूप में दिया था। 'राजा' के ताज को उतार कर 'प्रजा' के जीवन चरित्र धारण कर सबके बीच प्रजाभाव से काम करते रहना यह बिना ईश्वरीय व्यक्तित्व के संभव नहीं। इन्हीं कारणों से लगता है कि उनमें देवांश था। अगर देवांश नहीं होता तो प्रजा के रूप में अपने राजा के कार्य को देखने के लिए वे अखंड प्रवास नहीं करते। वे मूल में 'समाज प्रवर्तक' थे। यह ईश्वर की कृपा ही थी कि वे वहां भी गए, जहां उनके भाई का परिवार यानि मैसूर स्थित उनका पैतृक गांव है। फिर उन्होंने प्राणायाम करते हुए अपना शरीर वहां छोड़ा जिस रायपुर में उनका जन्म हुआ था।

मजेदार मामला है कि वे एक-डेढ़ माह पूर्व वहां भी गए थे जिस जबलपुर में उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। यह संयोग नहीं बल्कि देवांश था परिणाम था कि वे अपने पैतृक गांव भी गए। सबसे मिले भी। उसके बाद शिक्षा स्थान पर भी गए और जिस परिवार का एक-एक सदस्य संघ कार्य में लगा था, उनके कार्यक्रम में गए। वहां पर भी सभी नए पुराने लोग उन्हें मिले। फिर वे वहां गए जहां रायपुर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने शरीर वहीं छोड़ा, जहां ईश्वर ने उन्हें शरीर दिया था। यह सामान्य घटना नहीं है यह तब होता है जब कोई असामान्य होता है। सच में वे असामान्य थे। ■

दो उपलब्धियां, एक अपेक्षा

लालकृष्ण आडवाणी

blog.lkadvani.in

इन् 1992 में, प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी फ्रांसिस फुकुयामा ने एक पुस्तक लिखी थी "दि एण्ड ऑफ हिस्ट्री एण्ड दि लास्ट मैन।'' फुकुयामा का तर्क था कि नब्बे के दशक के अंत में दुनियाभर में उदार लोकतंत्रों का प्रसार मानवता के सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन का अंतिम बिन्दु है। मुख्य रुप से वह कम्युनिज्म के पतन का संदर्भ दे रहे थे। इसे इतिहास का अंत कहना शायद अतिश्योक्ति हो। लेकिन 1989 में बर्लिन दीवार का ढहना निस्संदेह वैश्विक इतिहास में एक विलक्षण मोड़ था। इसने लोकतंत्रों के प्रभुत्व और अमेरिकी तथा सोवियत ब्लॉकों के बीच चल रहे शीत युद्ध में वाशिंगटन की विजय को रेखांकित किया।

1989 भारत के राजनीतिक इतिहास का भी एक निर्णायक मोड़ रहा। इस वर्ष के लोकसभाई चुनावों में भाजपा ने एक लम्बी छलांग लगाते हुए दयनीय दो सीटों 1984 से में 86 सीटों 1989 का सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। भाजपा राष्ट्रीय राजनीति पर कांग्रेस पार्टी के एकाधिकार को चुनौती देने वाले मुख्य दल के रुप में उभरी।

अगले दशक में भाजपा 1996 तक, तेजी से बढ़ती रही और कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती गई, जब भाजपा लोक सभा में सर्वाधिक बड़े दल के रूप में उभरी, और 1998-1999में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण संभाल लिया और इसने 6 वर्षों तक देश को एक स्थिर, अच्छी सरकार और विभिन्न क्षेत्रों में अर्थपूर्ण प्रगति करने वाली सरकार दी। तब से, जब भी कोई मुझसे पूछता है: राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के मुख्य योगदान को आप कैसे निरुपित करेंगे तो सदैव मेरा उत्तर रहता है: भारत की एकदलीय प्रभुत्व वाली राजनीति को द्विध्रुवीय राजनीति में परिवर्तित करना।

अगले दशक में भाजपा 1996 तक, तेजी से बढ़ती रही और कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती गई, जब भाजपा लोक सभा में सर्वाधिक बड़े दल के रूप में उभरी, और 1998-1999में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण संभाल लिया और इसने 6 वर्षों तक देश को एक स्थिर, अच्छी सरकार और विभिन्न क्षेत्रों में अर्थपूर्ण प्रगति करने वाली सरकार दी। तब से, जब भी कोई मुझसे पूछता है: राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के मुख्य योगदान को आप कैसे निरुपित करेंगे तो सदैव मेरा उत्तर रहता है: भारत की एकदलीय प्रभुत्व वाली राजनीति को द्विध्रुवीय राजनीति में परिवर्तित करना।

मैं मानता हूं कि यह उपलब्धि न केवल भाजपा अपितु कांग्रेस और निस्संदेह देश तथा इसके लोकतंत्र के लिए वरदान सिद्ध हुई है दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी इसे इस रुप में नहीं लेती, भाजपा को एक मुख्य विपक्ष मानकर जिसके साथ सतत् संवाद करना शासन के लिए लाभकारी हो सकता है के बजाय इसे एक शत्रु के रूप में मानती है जिसे हटाना और किसी भी कीमत पर मिटाना उसका लक्ष्य है।

प्रणव मुकर्जी अपवाद थे। नेता लोकसभा के रूप में यूपीए के अधिकांश कार्यकाल में उन्होंने मुख्य विपक्ष के नेतृत्व से निरंतर संवाद बनाए रखा।

अत: जब हाल ही में कोयला सम्बन्धी सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी ने सीएजी पर गैर-जिम्मेदार और निंदात्मक टिप्पणियां की तो, हमने उनसे मिलने का फैसला किया तथा उनसे अनुरोध किया कि वे अपने पूर्ववर्ती सहयोगियों को कुछ सही सलाह दें।

श्री एम. हिदायतुल्ला द्वारा सम्पादित दो खण्डों वाले कांस्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इण्डिया में मुझे 1953 में डा. भीमराव अम्बेडकर द्वारा संसद में दिए गए भाषण को पढ़ने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने न केवल नियंत्रक और महालेखाकार को "भारत के संविधान में संभवतया सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी'' वर्णित किया है अपितु इस पर भी खेद प्रकट किया है कि उन्होंने उसे अपना दायित्व ढंग से निभाने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं।

डा. अम्बेडकर कहते हैं:

"यदि इस अधिकारी को अपनी ड्यूटी निभानी हो-और उनकी ड्यूटी, मैं मानता हूं कि न्यायपालिका से भी किसी भी हालत में कम नहीं है, वह भी न्यायापालिका की तरह निश्चित रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन, सर्वोत्तम न्यायलय सम्बन्धी अनुच्छेदों और महालेखाकार सम्बन्धी अनुच्छेदों की तुलना करें, तो मैं यही कह सकता हूं कि हमने उसे वैसी स्वतंत्रता नहीं दी है जैसी न्यायपालिका को दी है, यद्यपि मैं व्यक्तिगत रुप से महसूस करता हूं कि उसे न्यायपालिका की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता देने की जरुरत है।"

♦♦♦

जब मैं विगत् साठ वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन पर दृष्टि डालता हूं और यह अनुमान लगाने का प्रयास करता हूं कि जनसंघ और भाजपा की भारतीय राजनीति को दूसरी उपलब्धि क्या रही, तो मैं कह सकता हूं कि त्रासद आपातकाल के विरुद्ध लड़ने और लोकनायक जयप्रकाश का सहयोग करना। इस संदर्भ में जनसंघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश की राजनीति आज एक ऐसे बिन्दु पर पहुंची है जहां 'कोलगेट' के मुद्दे को एनडीए ने संसद में सशक्त ढंग से उठाया और अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर गंभीर रुख लिया है। 'कोलगेट' एक ऐसा घोटला है, जिसके बारे में सीएजी ने कहा है कि इससे सरकार को 1.86 लाख करोड़ का नुक्सान हुआ है। यह तथ्य है कि सीएजी ने जिस अवधि के कोयला मंत्रालय की समीक्षा की है उस काल में यह मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था और जिसके चलते 2जी और 2008 के कॉमनवेल्थ घोटाले से शुरु हुई घोटालों की शृंखला अपनी अति पर पहुंची है।

♦♦♦

जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस 'कोलगेट' घोटाले से सम्बन्धित छ: मुख्य सवाल सरकार से पूछे हैं, उसी दिन सरकार ने मल्टीब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सम्बन्धी निर्णय घोषित किया-इसे कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के हताशा भरे प्रयास के रुप में लिया गया। यदि वास्तव में सरकार ऐसा सोचती है तो यह उसकी गंभीर गलती होगी। न्यायपालिका, सीएजी और संसद में विपक्ष ने मीडिया के साथ जुटकर यह सुनिश्चित कर दिया है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा आगामी लोकसभाई चुनावों तक लोगों के दिमाग में बना रहेगा। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुद्दा वास्तव में यूपीए के लिए हराकरी के सिवाय और कुछ सिद्ध नहीं होगा।

मैं गंभीरता से आशा करता हूं कि जिस प्रकार 1977 के चुनाव परिणामों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि इसके बाद कोई भी सरकार अनुच्छेद 352 के आपातकाल प्रावधान का हल्के दुरुपयोग के बारे में सोचेगी भी नहीं, उसी प्रकार आने वाले विधानसभाई और लोकसभाई चुनाव भी राजनीतिज्ञों का इसका अहसास कराएंगे कि यदि मतदाता उनके हाथों को भ्रष्टाचार से सना देखेगा तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

अपने पूर्ववर्ती एक ब्लॉग में मैंने कहा था कि कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि आने वाले लोकसभाई चुनावों में कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा मात्र दो अंकों में सिमट जाए और इससे सबसे ज्यादा फायदे में भाजपा रहेगी। यदि और जब भी ऐसा होता है तो भाजपा इसे अपनी तीसरी उपलब्धि का दावा कर सकती है:एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम।■

जब मैं विगत् साठ वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन पर दृष्टि डालता हूं और यह अनुमान लगाने का प्रयास करता हूं कि जनसंघ और भाजपा की भारतीय राजनीति को दूसरी उपलब्धि क्या रही, तो मैं कह सकता हूं कि त्रासद आपातकाल के विरुद्ध लड़ने और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सहयोग करना। इस संदर्भ में जनसंघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कांग्रेस की विदाई का वक्त

✍ हृदयनारायण दीक्षित

सत्ता और अर्थनीति लोकहित के ही उपकरण हैं। इसी तरह आर्थिक सुधार भी। राजनीति ही अर्थनीति को लागू करने का माध्यम है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के ही विद्वान हैं, लेकिन सत्ता संचालन के लिए वह सोनिया गांधी से निर्देशित हैं। देश और राजनीति की नासमझी ही प्रधानमंत्री पर भारी पड़ी है। खुदरा व्यापार में एफडीआइ, डीजल में मूल्यवृद्धि और रसोई गैस में सब्सिडी की कटौती को आर्थिक सुधार बताने वाले प्रधानमंत्री की सरकार आइसीयू में है। राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है। बाजार के बड़े खिलाड़ी खुश हैं, लेकिन भारत बंद रहा। मनमोहन सिंह बाजार हित में लड़ते हुए शहीद होने के मूड में हैं। वह भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए देसी मीडिया व पक्ष-विपक्ष की आलोचनाएं झेल रहे थे। आर्थिक सुधारों आदि को लेकर विदेशी मीडिया ने उन्हें असफल बताया था। उन्होंने खामोशी को ही स्वर्णसूत्र बताया था, लेकिन अब खामोशी के दिन गए। उन्होंने कहा कि बड़े आर्थिक सुधारों का समय आ गया है, सरकार को जाना ही है तो कुछ दिखाकर जाए। बात साफ है कि सरकार जाए तो जाए बाजार घाटा क्यों उठाए?

बाजार की खुशहाली ही सरकार का दायित्व है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि बड़े आर्थिक सुधारों का वक्त अब क्यों आया है? पहले क्या कठिनाई थी? क्या 2जी, कामनवेल्थ कोयला घोटाला, महंगाई और भ्रष्टाचार की आलोचना से ध्यान बंटाने के लिए ही प्रधानमंत्री ने इसे उचित समय कहा है। आर्थिक सुधार की परिभाषा भी प्रधानमंत्री ने नहीं बताई।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पहले से ही जनविश्वास खो चुकी थी। ताजा घोषणा के जरिये प्रधानमंत्री ने राजनीतिक अस्थिरता को ही न्यौता दिया है। ममता निर्मम हो गईं, मानमनौव्वल के विकल्प सीमित हैं। सपा और बसपा का अपना एजेंडा है। ममता का एजेंडा सार्वजनिक है, लेकिन सपा और बसपा को पाले में रखने के लिए बड़ी कीमत की दरकार होगी। देखा-देखी द्रमुक भी आंख दिखाए तो बेजा क्या है? भारत के सामने तमाम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां हैं। अस्थिर सरकार का इकबाल नहीं होता। कांग्रेस बेशक गलत तरीकों से बहुमत जुटाती रही है, लेकिन सरकारों की बदनामी भी कम नहीं हुई।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

प्रधानमंत्री की घोषणाओं से समूचे देश में हड़कंप है। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लगभग 7-8 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने के खतरे हैं। 20-25 लाख नए रोजगार सृजन की ही संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसके पहले तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद को आश्वस्त किया था कि खुदरा व्यापार में एफडीआइ आम सहमति से ही लागू होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने सहयोगी दलों को भी विश्वास में नहीं लिया। डीजल की मूल्यवृद्धि का असर चक्रानुवर्ती होता है। इसका असर पड़ चुका है। परिवहन सेवाएं और माल ढुलाई महंगी हो चुकी हैं। महंगाई को नए पंख लगे हैं। रसोई गैस की कटौती से हरेक घर में आंसू हैं। देश इस सबके लिए तैयार नहीं था। राजनीतिक वातावरण खिलाफ है।

विपक्षी राजग के साथ गैरसंप्रग दल भी मैदान में हैं। सत्तारूढ़ घटक तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन वापसी की घोषणा की है। दूसरे घटक द्रमुक ने भी विरोध किया है। बाहर से समर्थन दे रही सपा व बसपा ने भी आलोचना की है। सरकार की घोषणा वस्तुतः कांग्रेस की ही घोषणा है, इन फैसलों को संप्रग के घटक दलों का भी समर्थन नहीं है। सरकार इस घोषणा को लेकर अल्पमत में है।

प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पहले से ही जनविश्वास खो चुकी थी। ताजा घोषणा के जरिये प्रधानमंत्री ने राजनीतिक अस्थिरता को ही न्यौता दिया है। ममता

निर्मम हो गई, मानमनौव्वल के विकल्प सीमित हैं। सपा और बसपा का अपना एजेंडा है। ममता का एजेंडा सार्वजनिक है, लेकिन सपा और बसपा को पाले में रखने के लिए बड़ी कीमत की दरकार होगी। देखा-देखी द्रमुक भी आंख दिखाए तो बेजा क्या है? भारत के सामने तमाम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां हैं। अस्थिर सरकार का इकबाल नहीं होता। कांग्रेस बेशक गलत तरीकों से बहुमत जुटाती रही है, लेकिन सरकारों की बदनामी भी कम नहीं हुई। नरसिंह राव की सरकार में समर्थक दल के कुछेक सांसद समर्थन की कीमत वसूलने के आरोपी थे।

मनमोहन सिंह की सरकार में ही ''वोट के बदले नोट'' का वीभत्स आचरण हुआ। केंद्र के सामने बहुमत बनाए रखने की चुनौती है। प्रधानमंत्री के बयान पर विश्वास करें तो वह लड़ते हुए सरकार गंवाने को तैयार हैं।

प्रधानमंत्री के साहस के कोई तो कारण होंगे। वरना जानबूझकर अपनों को ही अलग करने वाले फैसलों का तुक क्या है? विदेशी पूंजी का स्वागत मनमोहन-अर्थशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत है। डॉ. सिंह का अर्थशास्त्र अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन की उधारी है।

1970 के दशक में फ्रीडमैन की ही अगुवाई में विदेशी पूंजी का स्वागत और समाज कल्याण की योजनाओं पर धन न खर्च का काम हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने भी यही अर्थनीति आगे बढ़ाई थी, लेकिन भारत ने इसे पसंद नहीं किया। 1717 में मुगल सम्राट ने शाही फरमान के जरिये ईस्ट इंडिया कंपनी को करमुक्त आंतरिक व्यापार की छूट दी थी। कंपनी ने देश लूटा। कंपनी विदेशी पूंजी लाई, विदेशी पूंजी के साथ साम्राज्यवाद भी आया था। भारत का कच्चा माल विदेश गया। बेशक नए अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विदेशी पूंजी को अछूत नहीं माना जाता, लेकिन व्यापार और बाजार को सर्वथा मुक्त करना और स्वदेशी उद्यम को कमतर करना भारत के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। स्वदेशी और विदेशी व निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कोई संतुलन तो बनाना ही होगा।

दरअसल कांग्रेस ऐसे राष्ट्रीय प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री पहले ही थक चुके थे। भ्रष्टाचार और महंगाई के आरोपों से कांग्रेस की नींद हराम थी ही कि कोयला घोटाले के पर्दाफाश से कांग्रेस बेहद डर गई। संसद, सर्वोच्च न्यायपीठ और फिर कैग सहित तमाम संवैधानिक संस्थाओं की टिप्पणियों से कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस ने कैग पर भी हमले किए।

मुद्दा बदलना जरूरी था। प्रोन्तियों में आरक्षण के विधेयक से मुद्दा बदलने की कोशिश व्यर्थ रही। सो डीजल, रसोई गैस और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश जैसे अतिविवादित निर्णय सामने हैं। कोयला घोटाला पीछे भले ही हो गया हो, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा, उल्टे घटक दल भी ताजा निर्णयों को लेकर पीछा छुड़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री और कांग्रेस बुरे फंसे हैं। मुद्दा बदलने के बदले राजनीतिक अस्थिरता ही हाथ लगी है। ताजा अस्थिरता खतरनाक है। संप्रग एकजुट नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने गठबंधन के साथ-साथ देश का विश्वास भी खो दिया है। सोनिया का नेतृत्व असफल हो गया है। केंद्र के सामने दो ही विकल्प हैं। पहला यह कि मोलभाव की सरकार चलाएं। कभी इनको समझाएं और कभी उनको। दूसरा विकल्प है कि अपने घटक दलों, विपक्ष और आमजनों से लड़ते हुए प्रायश्चितपूर्ण विदाई लें। राव की तरह अपने अनुभवों पर किताब लिखें। नए चुनाव हों, नई सरकार आए। राजग पहले से उनका त्यागपत्र मांग रहा है।

प्रधानमंत्री और कांग्रेस बुरे फंसे हैं। मुद्दा बदलने के बदले राजनीतिक अस्थिरता ही हाथ लगी है। ताजा अस्थिरता खतरनाक है। संप्रग एकजुट नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने गठबंधन के साथ-साथ देश का विश्वास भी खो दिया है। सोनिया का नेतृत्व असफल हो गया है। केंद्र के सामने दो ही विकल्प हैं। पहला यह कि मोलभाव की सरकार चलाएं। कभी इनको समझाएं और कभी उनको। दूसरा विकल्प है कि अपने घटक दलों, विपक्ष और आमजनों से लड़ते हुए प्रायश्चितपूर्ण विदाई लें।

मुलायम सिंह को भी जल्दी चुनावों से ही फायदा होने वाला है। 2014 तक यूपी की सरकार अलोकप्रिय हो जाएगी। केंद्र को मुलायम का समर्थन भी आगामी चुनाव की उनकी तैयारी तक ही मिलने वाला है। कांग्रेस की विदाई का मौसम है। भविष्य की बातें चुनाव नतीजे बताएंगे। ■

(लेखक भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं)

(दैनिक जागरण से साभार)

राजनीति का खतरनाक रूप

✍ ए. सूर्यप्रकाश

असम के लोगों के लिए पिछले कुछ हफ्ते भयावह रहे हैं। गैर-कानूनी बाग्लादेशी अप्रवासियों और बोडो समुदाय के बीच हिंसक झड़पों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। यदि आप सोच रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार सीमापार से आ रहे इस खतरे को रोकने के प्रयास कर रही हैं तो आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और केंद्र सरकार वास्तविकता स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हैं।

मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि असम में आ रहे जनसांख्यिकीय बदलाव का बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ से कोई लेना-देना नहीं है। यह वोट बैंक की घटिया राजनीति और अवसरवादिता का नमूना है। पिछले दिनों एक टीवी चौनल को दिए साक्षात्कार में गोगोई ने कहा था, राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम निरक्षर हैं और उनके हर परिवार में छह से दस सदस्य हैं। मुख्यमंत्री को यह भी नहीं लगता कि घुसपैठियों की पहचान के लिए बने न्यायाधिकरण प्रभावी हैं। उनके मुताबिक ऐसे न्यायाधिकरणों में तीन लाख मामले हैं। इनमें से ज्यादातर रद कर दिए गए हैं, क्योंकि यह साबित करना बेहद मुश्किल है कि वे विदेशी हैं। अब कोई गोगोई से यह पूछे कि वह इसी देश के नागरिक हैं और असम में उनका स्थाई निवास है या फिर उन्हें यहां की जमीनी हकीकत का अहसास ही नहीं हैं? दक्षिण का एक सामान्य व्यक्ति भी आज असम में सीमापार से हो रही घुसपैठ से परिचित है। मुख्यमंत्री से यह सवाल इसलिए भी किया जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों से होने वाले खतरे को पहले ही रेखांकित किया जा चुका है।

नवंबर 1998 में असम के तत्कालीन राज्यपाल एसके सिन्हा ने ऐसे ही खतरे से आगाह करती एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि यदि जनसांख्यिकी के इस हमले को नहीं रोका गया तो गैर कानूनी घुसपैठिए असम के स्थानीय लोगों का सूपड़ा साफ कर डालेंगे। हो सकता है कि उत्तर-पूर्व बाकी भारत से कट ही जाए। उस रिपोर्ट में जनरल सिन्हा ने आगाह किया था कि असम में यह जनसांख्यिकीय हमला कई दशकों से चल रहा है और सरकारें इसे रोकने में नाकाम रही हैं। शुरुआती सालों में इसे स्थानीय समस्या के तौर पर लिया गया और इस अदूरदर्शी विचार का ही नतीजा हुआ कि सरकार ने इस बदलाव के दूसरे पहलू को नजरअंदाज कर दिया। तब सिन्हा ने कहा था असम की भू-सामरिक महत्ता, बांग्लादेश की बढ़ती आबादी और बढ़ता अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक रूढ़िवाद सीमापार से हो रही इस घुसपैठ से आने वाली खतरनाक परिस्थिति को रेखांकित करता है। इसके मद्देनजर हमें पंथनिरपेक्षता के ऐसे गुमान में नहीं रहना चाहिए कि इस सच्चाई को देख ही न सकें। सिन्हा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के एक बड़े मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ने पर अफसोस जताया था। उनके बाद 2005 में सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की बेंच ने भी यह मुद्दा उठाया। जस्टिस आरसी लाहोटी, जीपी माथुर और पीके बालासुब्रमण्यम ने जनरल सिन्हा की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर कहा था कि उप सेना प्रमुख का पद संभालने वाले शख्स की यह रिपोर्ट देश में बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी बताने के लिए पर्याप्त है।

नवंबर 1998 में असम के तत्कालीन राज्यपाल एसके सिन्हा ने ऐसे ही खतरे से आगाह करती एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि यदि जनसांख्यिकी के इस हमले को नहीं रोका गया तो गैर कानूनी घुसपैठिए असम के स्थानीय लोगों का सूपड़ा साफ कर डालेंगे। हो सकता है कि उत्तर-पूर्व बाकी भारत से कट ही जाए। उस रिपोर्ट में जनरल सिन्हा ने आगाह किया था कि असम में यह जनसांख्यिकीय हमला कई दशकों से चल रहा है और सरकारें इसे रोकने में नाकाम रही हैं।

बेंच ने कहा था कि राज्यपाल की रिपोर्ट, हलफनामे और दूसरे दस्तावेज बताते हैं कि लाखों बांग्लादेशी गैर कानूनी रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके आ गए हैं और असम की जमीन पर अपना अधिकार जमा लिया है। अदालत ने तब कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण असम बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति का सामना कर रहा है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वह असम को उचित सुरक्षा मुहैया कराए। जनरल सिन्हा और तीन जजों की इस बेंच के अलावा और भी बहुतेरे ऐसे प्रमाण हैं जो इस तरह की घुसपैठ की पुष्टि करते हैं। विदेशी नागरिकों के संदर्भ में राज्य में सक्रिय न्यायाधिकरणों ने चार लाख घुसपैठियों का पता लगाया है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट भी कहती हैं कि उनमें से एक को भी वापस बांग्लादेश नहीं भेजा गया। वे सभी हमारे बीच घुल मिल गए। इसके कई कारण हैं। जैसे विदेशियों के लिए बना कानून किसी भी संदिग्ध विदेशी को तब तक हिरासत में लेने की इजाजत नहीं देता जब तक उन पर न्यायाधिकरण अपना फैसला न दे दे। फिर न्यायाधिकरण द्वारा किसी संदिग्ध को घुसपैठिया घोषित कर दिए जाने के बाद भी वे हमारी सुस्त न्याय प्रणाली का लाभ उठा लेते हैं। वे अपील करते हैं और अक्सर गायब हो जाते हैं। यदि भारत कुछ मामलों में किसी निर्णय पर पहुंचता भी है तो फिर दूसरी अड़चनें सामने आ जाती हैं। मसलन, भारत की बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है और इसीलिए उन पर मुकदमा चलाना भी कठिन है। फिर चूंकि उनकी पहचान की भी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए उन्हें वापस भेजने में भी उतनी ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस तरह सीमापार की ये घटनाएं बेलगाम हो गई हैं और अब भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनकर खड़ी हैं।

जब मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दूसरे नेता कहते हैं कि जनसांख्यिकी में बदलाव घुसपैठियों के कारण नहीं हो रहा है तो आप उनके भोलेपन पर मत जाइएगा। यह गलती न ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वे तो अपना काम कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाने के लिए लगातार प्रयासरत रहने वाले गोगोई और उनकी पार्टी घुसपैठियों को शह देती आई है और उन्हें अपना वोट बैंक मानती है। तमाम रिपोर्टों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद साफ है कि सत्ता के लिए देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गोगोई और उनकी कांग्रेस के लिए प्राथमिकताओं का क्रम तय है। उनके लिए सबसे पहले है अपना हित, फिर आता है पार्टी हित और जब ये दोनों पूरे हो जाएं तो उसके बाद नंबर आता है राष्ट्रहित का।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पिछले 30 सालों में देश के कई जिलों में इस तरह के जनसांख्यिकीय बदलाव आए हैं कि उनमें अपने ही देश के नागरिक अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। ऐसे जिलों में बरपेटा, गोलपाड़ा, धुबड़ी, हेलाकंडी, करमगंज और नौगाव जैसे कुछ नाम शामिल हैं। इन तमाम पहलुओं और तथ्यों के प्रकाश में हमें गोगोई के बयान पर क्या कहना चाहिए? जब मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दूसरे नेता कहते हैं कि जनसांख्यिकी में बदलाव घुसपैठियों के कारण नहीं हो रहा है तो आप उनके भोलेपन पर मत जाइएगा। यह गलती न ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वे तो अपना काम कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाने के लिए लगातार प्रयासरत रहने वाले गोगोई और उनकी पार्टी घुसपैठियों को शह देती आई है और उन्हें अपना वोट बैंक मानती है। तमाम रिपोर्टों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद साफ है कि सत्ता के लिए देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गोगोई और उनकी कांग्रेस के लिए प्राथमिकताओं का क्रम तय है। उनके लिए सबसे पहले है अपना हित, फिर आता है पार्टी हित और जब ये दोनों पूरे हो जाएं तो उसके बाद नंबर आता है राष्ट्रहित का। ■

(दैनिक जागरण से साभार)

नलिन कोहली बने भाजपा के प्रचार प्रभारी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 16 सितम्बर 2012 को पार्टी राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य श्री नलिन सत्यकाम कोहली को प्रचार विभाग का प्रभारी नियुक्त किया है। विदित हो कि श्री कोहली 2006- 2009 तक भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व संभाल चुके हैं।

हमारा लक्ष्य सभी लोगों के लिए समानता सुनिश्चित करना है : गडकरी

Hkkरतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा ने 17 सितम्बर 2012 को अखिल भारतीय पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया। 30 से अधिक राज्यों से 10,000 पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया जो मण्डल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने किया।

अपने उद्घाटन भाषण में श्री नितिन गडकरी ने कहा कि 21वीं सदी के विकासात्मक मुद्दे हमारे लिए राजनीति के प्रमुख एजेण्डा है। ''हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। बेहतर सुशासन और विकास हमारा प्रमुख मुद्दा है।'' उन्होंने आगे कहा कि जनसंघ के समय के दौरान एक अफवाह फैलाई गई थी कि कांग्रेस और जनसंघ दलित-विरोधी, गरीब-विरोधी और पिछड़ा वर्ग-विरोधी संस्थाएं हैं। निश्चित ही यह सत्य नहीं था। अंत्योदय की अवधारणा (अर्थात् समाज की पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति) का सपना तो स्वयं हमारे प्रमुख विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था, जो हमारे लिए राजनीतिक आंदोलन चलाने में एक प्रेरक मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने ही भारतीय जनसंघ को और बाद में भारतीय जनता पार्टी को प्रेरणा दी। सच तो यही है कि केवल भाजपा ही दलितों का ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि हमारा तो प्रमुख लक्ष्य ही हर स्तर पर सभी लोगों के लिए समानता सुनिश्चित करना है। उन्होंने उल्लेख किया कि 21वीं शताब्दी का राजनीतिक विकास, बायोटैक्नालॉजी और प्रशिक्षण आधारित है। भाजपा बेहतर सुशासन और विकास पर ध्यान देना चाहती है। राजनीति में निर्णय लेना, निर्णय कार्यान्विति, बेहतर नेतृत्व और दूरदृष्टिगत नेतृत्व जैसे बातों का राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान

होता है। केन्द्र के वर्तमान कांग्रेस सरकार की पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले भाजपा-नीत एनडीए सरकार से तुलना करते हुए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार-मुक्त थी, लोगों के प्रति जवाबदेह के साथ-साथ पारदर्शी थी परन्तु वर्तमान सरकार ने सारी सीमाएं लांघ ली है जिससे अब इस सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक हो गया है। उन्होंने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का विरोध करते हुए कहा कि जिस देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हों, उस देश में इस प्रकार का निवेश की अनुमति देना कोई अच्छा कदम नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस नव-उदारवादी सरकार के शासन में गरीबों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हम गरीबी को उखाड़ फेंकने के लिए निवारणकारी उपाए करेंगे क्योंकि अधिकांश गरीब लोग अनुसूचित जाति समुदाय के ही होते हैं।''

इस अवसर पर भाजपा महासचिव श्री थावर चंद गेहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति से खेल रही है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि इस भ्रष्ट कांग्रेसी सरकार ने अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों को धोखा और गरीबी के सिवा कुछ भी तो नहीं दिया है। आज भारत की अनुसूचित जाति के लोगों की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गरीबी की जिंदगी बिता रही है।

भाजपा प्रवक्ता तथा पूर्व भाजपा अनु.जाति मोर्चा अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि कांग्रेस सदैव ही गलतबयानी कर तथ्यों को प्रस्तुत करती है। कहा जाता है कि केन्द्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनु. जाति के लिए 15 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया है परन्तु पिछले नौ वर्षों से केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित पदों को कभी भर नहीं पाई है।■

गुजरात को गुटका-मुक्त और कांग्रेस-मुक्त बनाओ : नरेन्द्र मोदी

स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं तो राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रेरणा-पुरुष भी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता आंदोलन में जौहर दिखाए तो देश की आजादी के बाद युवाओं को प्रेरित करते हुए दूसरी आजादी का अलख जगाया। 11 सितम्बर ऐतिहासिक दिन है। सन् 1893 में इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाषण करते हुए पूरे विश्व का ध्यान भारत की सांस्कृतिक शक्ति की ओर खींचा। 11 अक्टूबर भी पावन दिन है। इस दिन जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस दोनों ऐतिहासिक दिनों को यादगार बनाते हुए 11 सितम्बर 2012 से 'विवेकानंद युवा विकास यात्रा' आरंभ किया, जिसका समापन 11 अक्टूबर 2012 को संपन्न होगा। इस यात्रा के दौरान जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोदी विभिन्न स्थानों पर जाकर युवाओं से संवाद कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के युवा भी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का बढ़-चढ़कर अभिनंदन कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जगह-जगह तोरणद्वार बनाए। जयकारों के बीच उनके रथ पर पुष्पवर्षा से उनका स्वागत किया जा रहा है। विभिन्न जगहों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता यात्रा के संदेश को फैलाने के लिए शामिल हो रहे हैं। अब तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली यात्रा में शामिल हो चुके हैं। इस अवसर पर श्री मोदी जहां प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए गए जनहितकारी कार्यों के बारे में लोगों को बता रहे हैं वहीं वह केंद्र की जनविरोधी नीतियों को लेकर यूपीए सरकार पर जमकर बरस भी रहे हैं। प्रस्तुत है संक्षिप्त विवरण:

चार्जी (मेहसाणा) में लोगों को संबोधित करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 9/11 दिवस पर दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इतिहास में अपने निशान छोड़ दिए। पहली घटना ट्विन टावर पर हमले की थी जिसमें अनेक निर्दोष लोग मारे गए, परन्तु 1893 में एक और 9/11 पर घटना घटी जब स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व का ध्यान भारत की सांस्कृतिक शक्ति की तरफ खींचा जब उन्होंने शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट आफ रिलीजन में अपना भाषण दिया।

श्री मोदी ने गुटका-मुक्त गुजरात का समर्थन किया और उसी क्रम में उन्होंने युवाओं को बचाने के लिए कांग्रेस-मुक्त गुजरात का भी आह्वान किया।

इससे पूर्व राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने इस

अवसर पर बोलते हुए गुजरात के विकास की तेज गति की सराहना की। श्री जेटली ने कहा कि सीबीआई गुजरात के राजनैतिक भाजपा नेताओं को परेशान करने में जुटी हुई है। श्री राजनाथ सिंह का कहना था कि आज गुजरात देश का मॉडल राज्य बन गया है, जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। इस अवसर पर जिन अन्य लोगों ने भाषण दिया उनमें भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम रूपाला और गुजरात अध्यक्ष श्री आर सी फाल्दू शामिल थे।

सरदार पटेल की जन्मभूमि गुजरात में कोई झूठ और चतुराई कारगर नहीं होगी

11 सितम्बर की सायं को श्री नरेन्द्र मोदी की विवेकानंद युवा विकास यात्रा सानंद पहुंची। भारी वर्षा के बावजूद भी श्री मोदी का भाषण सुनने के लिए वहां बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित था। अपने उद्‌बोधन में मुख्य मंत्री ने सरकार द्वारा किए गए विकास के पहल-उपायों का उल्लेख किया और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति पर फटकार लगाई। श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की जन्मभूमि पर किसी भी प्रकार का झूठ और चतुराई काम नहीं करेगी। श्री मोदी ने आश्वस्त किया कि गुजरात सरकार की नई वस्त्र नीति ने सांद-विरामगाम के हिस्से में गहरा परिवर्तन आएगा और लाखों युवाओं को नौकरियां मिलेंगी एवं वस्त्र उद्योग फले फूलेगा।

गुजरात मना रहा 'विकास दशक' तो कांग्रेस मना रही झूठ पर झूठ बोलने का दशक

श्री नरेन्द्र मोदी की स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा 11 सितम्बर 2012 को मेहसाना जिले के 'कडी' में प्रवेश किया। श्री मोदी ने विभिन्न मुद्‌दों पर बोले और लोगों को कांगेस की क्षुद्र राजनीति और गुजरात के प्रति उनके अन्याय से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कड़ी के लोगों का अत्यंत आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं जब भी यहां आता हूं तो मुझे आप लोगों का हर बार भव्य अभिनंदन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मुश्किल यह है कि यहां के लोगों के इस भव्य अभिनंदन को देखकर कांग्रेस परेशान हो जाती है, जिससे कांग्रेस की झूठ बोलने की मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरी खुल जाती है, फिर भी लोग उसके झूठ पर विश्वास नहीं करते हैं। श्री मोदी ने आगे कहा कि जहां गुजरात 'विकास दशक' मना रहा है, वहीं कांग्रेस 'झूठ पर झूठ' बोलने का दशक मना रही है।

उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने भी कोयला चुराए जाने की बात नहीं सुनी है परन्तु केन्द्र सरकार है कि उसने तो 2 लाख करोड़ रुपए की चोरीकर देश को पूरी तरह से लूट लिया है।

अब तो एआईसीसी का नाम हो गया है आल इण्डिया कोल कांग्रेस : श्री मोदी

दक्षिण गुजरात में श्री नरेन्द्र मोदी की एक दिन की विवेकानंद युवा विकास यात्रा पहुंचने पर वहां भारी जन समूह उपस्थित था। नवसारी जिले के उनाल में अपने श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने किसानों के हित में अनेक कदम उठाने की घोषणा की और कहा कि कांग्रेस अभी तक पिछले 60 वर्षो में निरंतर विभाजनकारी राजनीति पर चल रही है। श्री मोदी ने खरीफ की खेती करने वाले किसानों को 15 अगस्त 2012 तक के लिए कृषि ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज से राहत प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कृषि बिजली बिलों में भी 50 प्रतिशत राहत की घोषणा की।

बेतहाशा फैले भ्रष्टाचार के मुद्‌दे पर श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने यह तो सुना था कि स्वर्ण और हीरो की चोरी हो जाती है परन्तु कांग्रेस के लोगों ने तो राष्ट्र का कोयला चुरा कर देश को कलंकित कर दिया है। उनका कहना था कि अब तो लगता है कि एआईसीसी नाम का मतलब ही आल इण्डिया कोल कांग्रेस हो गया है।

धर्मपुर में विवेकानंद युवा विकास यात्रा का भव्य अभिनंदन

वलसाड जिले के धर्मपुर में विवेकानंद युवा विकास यात्रा का भव्य अभिनंदन हुआ, जब वह वहां 13 सितम्बर 2012 में पहुंची। अपने जोरदार भाषण में श्री मोदी ने गुजरात में आदिवासी समुदायों के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया और कांग्रेस पर झूठ फैलाने और नकारात्मक राजनीति पर कस कर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार विकास पथ पर चल रही है तो कांग्रेस झूठ मार्ग को गले लगा रही है।

यूपीए की जन-विरोधी नीतियों पर मुख्यमंत्री का कड़ा प्रहार

14 सितम्बर 2012 को विवेकानंद युवा विकास यात्रा के दौरान श्री मोदी ने कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की विनाशकारी और जनविरोधी नीतियों पर जम कर प्रहार किया।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूपीए ने डीजल की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी कर लोगों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बढ़ोतरी से केवल डीजल की कीमत नहीं बढ़ेगी बल्कि किसानों तथा अन्य लोगों को अन्य प्रकार से विपरीत प्रभाव झेलने पड़ेंगे।

श्री मोदी ने उतने ही जोरदार शब्दों में सब्सिडीयुक्त सिलेण्डरों पर भी राशन करने के लिए यूपीए सरकार को आड़े

हाथों लिया।

भावनगर में विवेकानंद युवा परिषद में मोदी का भाषण

15 सितम्बर 2012 के प्रात:काल, श्री नरेन्द्र मोदी ने भावनगर में विवेकानंद युवा विकास परिषद के युवाओं को सम्बोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का एक शक्तिशाली भारत बनाने का सपना था, परन्तु दुर्भाग्य से यूपीए सरकार की जन-विरोधी नीतियों ने इसे छिन्न-भिन्न कर दिया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार महुआ में पब्लिक अस्पतालों को अपने हाथ में लेगी, इन्हें चलाएगी और इन्हें जिला अस्पतालों का दर्जा देगी। श्री मोदी ने घोषणा की कि गुजरात सरकार 62 हॉस्टलों का एक नेटवर्क बनाएगी जिसमें 32,000 विद्यार्थियों को स्थान मिल सकेगा। उनकी तीसरी घोषणा यह थी कि महिलाओं हॉस्टलों का नेटवर्क का भी निर्माण होगा जिनमें औद्योगिक विकास के क्षेत्रों की 10,000 महिलाएं रह पाएंगी।

श्री मोदी ने कहा कि खुदरा बाजार में यूपीए सरकार कार्यान्वित करने जा रही एफडीआई का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं और कहा कि ऐसा समय आ गया है कि जिससे अब विदेशी लोग हमें चाय, किराने की अन्य वस्तुएं बेचेंगे और हमारे व्यापारियों की दुकानों पर ताले लग जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इससे बेरोजगारी फैलेगी और देश के युवा प्रभावित होंगे। भावनगर की धरती से श्री मोदी ने प्रधानमंत्री से सीधे-सीधे सवाल किया कि वह देश को बताए कि कितने इतालवी व्यापारी यहां आएंगे और अपनी दुकानें लगाएंगे और हमारे युवाओं पर इससे कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा?

विकास से समस्याएं सुलझेंगी

15 सितम्बर 2012 की मध्याह्न में विवेकानंद युवा विकास यात्रा भरूच जिले के आमोद में पहुंची। श्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि सभी समस्याओं का समाधान विकास ही है और उन्होंने भाजपा की विकास की दिशा की तुलना कांग्रेस की ''बांटो और राज करो'' की मानसिकता से किया। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व काल में भरूच जिले में बहुत कम विकास हो पाया था परन्तु आज यह उन जिलों में एक माना जाता है जहां कच्छ समेत सबसे अधिक तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सम्पूर्ण विकास केन्द्र से कोई मदद लिए बिना किया गया है, मुख्यमंत्री ने श्रोताओं से पूछा कि क्या वे इस विकास से संतुष्ट हैं, वह चाहे सड़कों का नाम हो या स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, कृषि किसी भी विभाग का काम हो तो लोगों ने समवेत स्वर में 'हां' कह कर अपना समर्थन प्रगट किया। परन्तु श्री मोदी ने उत्तर में कहा कि नहीं, मैं अभी भी खुश नहीं हूं क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वह तो कांग्रेस के 40 वर्षों में की गई बाधाओं को सही किया है, इसलिए अभी और बहुत कुछ करना बाकी है।

मध्य गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा का चौथे दिन भव्य स्वागत हुआ

चौथे दिन, 15 सितम्बर 2012 को श्री मोदी मध्य गुजरात के क्षेत्रों में गए, जिनमें कर्जन खडोदरा जिला, आमोद, जम्बुसर (भरूज जिला), बोरसाड, पेतलेड, तारापुर, खम्बाट (आनंद जिला) शामिल थे। युवा विकास यात्रा में सभी समुदायों के लोगों ने भाग लिया और श्री मोदी पर अपना समर्थन अभिव्यक्त किया। अपने प्रेरणादायी भाषण में श्री मोदी ने गुजरात में विकास की बात कही और यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति पर चल रही है।

राहुल गांधी जी कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नेता हैं जिनके पास भारत और इटली दोनों जगह चुनाव लड़ने की सुविधा है : श्री मोदी

17 सितम्बर को प्रात:काल में श्री मोदी ने राजकोट की विवेकानंद युवा परिषद को सम्बोधित किया। श्री मोदी ने सभी लोगों के प्रति अपना आभार और धन्यवाद प्रगट किया जिन्होंने उनके जन्मदिवस पर हार्दिक अभिनंदन किया है। उन्होंने साफ तौर पर खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का विरोध किया क्योंकि इससे युवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने ओलंपिक मेडल विजेता श्री गगन नारंग और क्रिकेटर रवीन्द्र जड़ेजा एवं जेतेश्वर पुजारा का अभिनंदन किया। उन्होंने विभिन्न युवाओं को स्पोर्ट्स किट भेंट किए।

एक कांग्रेसी नेता ने अपने बयान में टिप्पणी की थी कि श्री मोदी की तुलना एआईसीसी महासचिव श्री राहुल गांधी से नहीं हो सकती है क्योंकि वह तो केवल एक राज्य नेता है जबकि श्री गांधी एक राष्ट्रीय नेता है। श्री मोदी ने कहा कि मैं इस कांग्रेसी नेता के वक्तव्य की बात को केवल 50 प्रतिशत स्वीकार करता हूं कि मुझे तो गुजरात का नेता होने और लोगों की सेवा करने पर गर्व है। परन्तु, उन्होंने उस बयान के दूसरे हिस्से को खारिज करते हुए यह बात जोड़ी कि श्री राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नेता हैं जो भारत और इटली दोनों जगह से चुनाव लड़ सकते हैं।

अम्बाजी में विवेकानंद युवा विकास यात्रा, मुख्यमंत्री ने अरावली जिले के गठन की घोषणा की

17 सितम्बर 2012 को विवेकानंद युवा विकास यात्रा अम्बाजी कस्बे में मंदिर से अपना सफर तय करते हुए जारी

रही। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता की खातिर वोट इकट्ठा करने के लिए लोकतंत्र की भावना के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात के कारण ही कांग्रेस पिछले दशक से सत्ता से बाहर रही है और इसी कारण गुजरात ने प्रगति की नई ऊंचाईयां प्राप्त की हैं। उन्होंने इस अवसर पर अरावली में एक नया जिला और पोशीना का एक नया ताल्लुका गठन की घोषणा की।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के विकास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गुजरात का विकास पूरे विश्व की निगाहों में बोलता है। उन्होंने यूपीए की गलत नीतियों को भी आड़े हाथों लिया।

प्रधानमंत्री की लोकतंत्र की परिभाषा-विदेशियों की सरकार, विदेशियों द्वारा, विदेशियों के लिए

21 सितम्बर 2012 को भुज में विवेकानंद युवा परिषद के विशाल समूह को सम्बोधित करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने यूपीए सरकार की नीतियों की गहन भर्त्सना की। पूर्व अमरीकी प्रेजीडेण्ट अब्राहम लिंकन के मुहावरे का उद्धरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि असम की घटनाओं और खुदरा क्षेत्र में केन्द्र सरकार की एफडीआई की भूमिका को देखते हुए डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे संशोधित कर दिया है और यूपीए ने एक नई परिभाषा दी है- विदेशियों की सरकार, विदेशियों द्वारा और विदेशियों के लिए। पूर्व उप-प्रधानमंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी भी इस अवसर पर बोले। उन्होंने कच्छ के बारे में अपने सम्बंधों को जोड़ते हुए स्वामी विवेकानंद को हार्दिक श्रद्धांजलि प्रदान की। ■

मध्य प्रदेश में युवा संकल्प बाइक रैली

स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाने के लिए मध्य प्रदेश भाजयुमो ने इंदौर से राज्यव्यापी युवा संकल्प बाइक रैलियों का आयोजन किया। रैली के शुभारंभ अवसर पर आयोजित जनसभा को लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी श्री अनंत कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा तथा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सम्बोधित किया। इस प्रकार की रैली के उद्देश्य पर बोलते हुए प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रभात झा ने कहा कि ''भाजयुमो मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नई क्रांति ला रही है और यह क्रांति की शुरूआत का लाचिंग पैड है।'' इस यात्रा के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का संदेश और मध्य प्रदेश सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचते जाएंगे।

अभी तक ये रैलियां रीवा (26 अगस्त), उज्जैन (1 सितम्बर), जबलपुर (2 सितम्बर), ग्वालियर (9 सितम्बर), सागर (16 सितम्बर) में आयोजित हो चुकी हैं, यह 'महारैलियां'' 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भोपाल में जाकर सम्पन्न होंगी।

हिमाचल प्रदेश में 'युवा संकल्प रैली'

हिमाचल भाजपा ने हमीरपुर में युवा संकल्प रैली का आयोजन किया जिसमें राज्य के सभी महत्वपूर्ण भाजपा नेताओं के साथ-साथ पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार, मुख्य मंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल, श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने भाग लिया।

भाजपा ने किया झारखण्ड में 'कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ' रैली का आयोजन

12 सितम्बर को कल्हान में चायबास (छत्तीसगढ़) में भाजयुमो ने एक युवा रैली 'कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ' रैली का आयोजन किया। बारिश होने के बावजूद भी विशाल संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। रैली में बोलते हुए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि ''कांग्रेस पार्टी ने तो जमीनलोक, आकाशलोक और पाताललोक तक को बेच खाया है। झारखण्ड भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का श्री दिनेशानंद गोस्वामी ने भी रैली को सम्बोधित किया।

मध्यप्रदेश का सुशासन और यूपीए के घोटालों को लेकर जनता के बीच जाएं : अनंत कुमार

संवाददाता द्वारा

Hkkरतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक 11 एवं 12 सितम्बर 2012 को खंडवा में संपन्न हुई। बैठक का उद्घाटन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्यप्रदेश भाजपा प्रभारी श्री अनंत कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश देश में विकास, सुशासन और आदर्श संगठन का मॉडल बना है। यहां समृद्धि और विपुलता की क्रांति आई है, जिसने अन्य प्रदेशों समेत राष्ट्रीय औसत को पीछे धकेल दिया है। विकास का एजेंडा और कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार घोटालों को लेकर जनता के बीच जाये और कांग्रेस को प्रदेश से विसर्जित कर दें।

श्री अनंत कुमार ने मध्यप्रदेश में सरकार और संगठन की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, प्रदेश का पार्टी नेतृत्व, संगठन और कार्यकर्ता बधाई के पात्र है। मध्यप्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य में गिना जाता था लेकिन प्रदेश सरकार की गतिशील और क्रांतिकारी नीतियों नें प्रदेश को देश में विकास और सुशासन के मामलें में शीर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया है।

प्रदेश कार्यसमिति बैठक के प्रांरभ में राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, सांसद थावरचंद गेहलोत, नरेन्द्र सिंह तोमर, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर अहमद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, प्रदेश संगठन महामंत्री अरविन्द मेनन, जिला अध्यक्ष सुभाष कोठारी ने ध्वजारोहण एवं दीप प्रज्जवलन के साथ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता सिंधिया जी और कुशाभाऊ ठाकरे के चित्रों पर पुष्पाजंलि अर्पित की।

प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने अपने स्वागत भाषण में राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने के रास्ते पर अग्रसर है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कठोर परिश्रम, अखंड प्रवास के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे है। कार्यकर्ता विजयव्रती की भूमिका में लौहसंकल्प के साथ तत्पर है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां है। कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से हम मिशन-2013 और लोकसभा-2014 को सफल बनायेंगे।

बैठक का संचालन पार्टी के प्रदेश महामंत्री नंदकुमार सिंह चौहान ने किया। उक्त अवसर पर वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वरिष्ठ नेता डॉ. सत्यनारायण जटिया, विक्रम वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.गौरीशंकर शेजवार, वरिष्ठ मंत्री बाबूलाल गौर सहित प्रदेश पदाधिकारी, मंत्रिगण, सांसद, विधायक एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भी उपस्थित थे।

श्री अनंत कुमार ने कहा कि अटल जी ने देश में नदियों को जोड़कर बाढ़ और सूखा से मुक्ति का जो सपना देखा था उसे साकार रूप देने में देश में शिवराज सिंह चौहान की मध्यप्रदेश सरकार अग्रणी सिद्ध हुई है। अटल जी

ने देश की 32 प्रमुख नदियों को जोड़कर 8 करोड़ एकड़ में सिंचाई और 50 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का सपना देखा था। मध्यप्रदेश में प्रथम चरण में नदियों को जोड़कर 1 करोड़ एकड़ पर सिंचाई क्षमता के सृजन की कार्ययोजना प्रारंभिक चरण में है। इससे मध्यप्रदेश का पश्चिमी अंचल निमाड़ और मालवा हरा-भरा प्रदेश बन जायेगा। श्री अनंत कुमार ने केन्द्र सरकार के घोटालों की चर्चा करते हुए कहा कि देश में नदियों को जोड़ने पर 10 लाख करोड़ रू. की लागत का अनुमान बताया गया था, दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता में आने के बाद यूपीए सरकार ने नदी जोड़ो योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और खुद 2-जी स्पेक्ट्रम, कॉमलवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसायटी घोटाला, कोयला घोटाला और अन्य घोटालों में 10 लाख करोड़ रू. का गबन किया।

इस राशि से नदी जोड़ों योजना पूरी की जा सकती थी और देश का नक्शा बदला जा सकता था। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश में 8 वर्षों की उपलब्धियां विकास, सुशासन की शानदार मिसालों को दीपावली, होली के बाद गांव-गली में पहुंचकर चौपाल चर्चा बनाये और केन्द्र सरकार के घोटालों को जनता की अदालत में बेनकाब करें। उन्होंने 230 विधानसभा क्षेत्रों में विकास शिविर लगाने और गांव-गांव में संपर्क यात्रा आरंभ करने का आग्रह किया। उन्होनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनका सपना मध्यप्रदेश को स्वर्णिम राज्य बनाने का है।

शिवराज सिंह चौहान की यह सोच भी अनुकरणीय है कि राष्ट्र को स्वर्णिम बनाने के पहले प्रदेश का कायाकल्प होना जरूरी है। उन्होंने मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताते हुए प्रभात झा को बधाई दी और कार्यकर्ताओं को अतिउत्साह और अतिविश्वास से बचने की सलाह देते हुए कहा कि वे मिशन-2013 और लोकसभा-2014 की रणनीति बनाने में जुट जाएं।

श्री अनंत कुमार ने कहा कि लोगों का यह तर्क असंगत है कि संसद में हमने बहस का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने ही 2-जी स्पेक्ट्रम के मामले में संसद को ठप्प करके देश को 1 लाख 26 हजार करोड़ की आय अंकित कराई है। कोयला का घोटाला तो इससे कई गुना अधिक है जिससे देश की बहुमूल्य संपदा कोड़ियों को भाव बेच दी गयी है। कांग्रेस ने 2-जी स्पेक्ट्रम के समय संसद में जो वादा किया था उससे मुकर गयी और उसने संसदीय समिति का सामना नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में कांग्रेस का तर्क था कि यह गठबंधन सरकार की मजबूरी है और उसके लिए दोषी मंत्री जबावदेह होंगे। उनका बाद में इस्तीफा भी लिया गया। कोयला घोटाला ऐसे समय हुआ जब प्रधानमंत्री स्वयं कोयला मंत्री के प्रभार में थे तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। इस तर्क पर कांग्रेस निरूत्तर है।

मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए श्री अनंत कुमार ने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली, पानी एवं सड़क देने का वादा किया था। मध्यप्रदेश में बिजली का उत्पादन 3 हजार मेगावाट से बढ़कर 6 हजार मेगावाट हो गया है और आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में 12-13 हजार मेगावाट बिजली की क्षमता हो जायेगी। हम गुजरात के बाद देश में सबसे बड़े (मध्यप्रदेश) बिजली उत्पादक बन जायेंगे। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिले। इसके लिए मध्यप्रदेश में भरपूर प्रयास हो रहे है और आम आदमी के सामाजिक आर्थिक जीवन में सुखद परिवर्तन आ रहा है। देश के अन्य राज्यों में जहां पानी को लेकर परस्पर तकरार और तनाव की स्थिति है। मध्यप्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसने जल प्रबंधन में दूरदर्शिता का परिचय देते हुए महारत हासिल कर ली है। जल प्रबंधन की दृष्टि से मध्यप्रदेश में सिंचाई योजनाओं का जाल बिछाया जा रहा है। जो क्षमता 7 लाख हेक्टेयर सिंचन की थी उसे बढ़ाकर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जा चुका है। जो किसी भी राज्य से उत्कृष्ट है। इसी का नतीजा है कि मध्यप्रदेश हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति के मामले में आगे बढ़ा है। प्रदेश में कृषि की विकास दर 18 प्रतिशत से ज्यादा पहुंच गयी है और विकास दर में मध्यप्रदेश ने देश को पीछे छोड़ दिया है।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र के पश्चात राजनैतिक प्रस्ताव प्रदेश महामंत्री राकेश सिंह ने प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के सुशासन की दिशा में उठाये गये क्रांतिकारी कदमों और संगठन के प्रभावी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए निंदा की। प्रस्ताव का समर्थन वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया।

प्रस्ताव पर उपस्थितजनों ने विस्तार से चर्चा की। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने कृषि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। केन्द की यूपीए सरकार द्वारा किए गए घोटालों पर केन्द्रित प्रस्ताव भी सर्वसम्मति पारित किए गए, जिसे प्रदेश मंत्री व सांसद श्री गणेश सिंह ने प्रस्तुत किया। ■